हिन्दी दैनिक...

विकास वार्ता

सत्य • निष्पक्ष • निर्भीक

शनिवार, 12 सितंबर 2026 | संस्करण बेगूसराय | वर्ष 01 | अंक 295 | पृष्ठ 08 | मूल्य ₹ 2/- | RNI No : BHHIN/25/A2044 | https://vikasvaarta.com

बिहार के भागलपुर में दो जगह तटबंध टूटे, कोसी के बढ़ते जलस्तर से बढ़ी चिंता

पटना, संवाददाता। बिहार के भागलपुर जिले में बाढ़ की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। कोसी नदी के तेज दबाव और भारी बारिश के बीच दो अलग-अलग जगहों पर तटबंध टूट गई है। नौगछिया के रंगरा चौक ब्लॉक के बनिया गांव में पुरानी रेलवे लाइन के तटबंध का करीब 15 मीटर हिस्सा कोसी के बाढ़ के पानी के दबाव में ढह गया। टूटे हुए हिस्से से पानी तेजी से आसपास के इलाकों की ओर बह रहा है, जिससे साधोपुर, मसुदनपुर, बैसी, भवानीपुर और बनिया के लोगों में डर बढ़ गया है। स्थानीय प्रशासन और लोग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी आसपास के इलाकों पर दबाव डाल रहा है। दूसरी घटना नौगछिया के गोपालपुर में हुई, जहां ब्रह्मोत्तर तटबंध में लगभग 10 मीटर का कटाव हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार देर रात आंधी और बारिश के बाद यह हिस्सा टूट गया। प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर स्थिति को काबू में करने और आगे नुकसान रोकने के लिए काम तेज कर दिया है। इस तटबंध को लेकर चिंता पहले से ही थी, क्योंकि चार दिन पहले यहां रिसाव देखा गया था। 10 मीटर हिस्से के ढहने के बाद अब डर है कि बड़ा कटाव होने पर गोपालपुर की बड़ी आबादी प्रभावित हो सकती है। लगातार बाढ़ के कारण बड़ी संख्या में परिवारों को अपना घर

छोड़कर राहत शिविरों में जाना पड़ा है। फिलहाल प्रभावित इलाकों में 27,954 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल ने कहा कि जो परिवार पिछले पांच दिनों से बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें 7,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह मदद लंबे समय से विस्थापन झेल रहे परिवारों को तत्काल सहारा देने के लिए है। बाढ़ ने शिक्षा व्यवस्था को भी बिगाड़ दिया है। कोसी क्षेत्र के करीब 5,000 स्कूलों में पानी भर गया है, जिससे हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कई जगहों पर स्कूल की इमारतों को राहत और बचाव कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पढ़ाई और ज्यादा बाधित हो गई है। सुपौल में कोसी नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर बताया जा रहा है। शुक्रवार सुबह 6 बजे कोसी बराज से करीब 1.41 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि बराह क्षेत्र से 1.07 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। जलस्तर स्थिर होने के बावजूद अधिकारी नदी के जलस्तर और दबाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भागलपुर में ताजा तटबंध टूटने और बिहार के बड़े हिस्से में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी होने से प्रशासन और स्थानीय लोग आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की आशंका को लेकर अलर्ट पर हैं।

वैश्विक व्यापार निर्यात में ब्रिक्स देशों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 24 प्रतिशत हो गई है: पीयूष गोयल

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि वर्ष 2003 में ब्रिक्स देशों का वैश्विक निर्यात लगभग 900 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2024 में करीब 6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। इसी अवधि में वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित 'ब्रिक्स बिजनेस फोरम 2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, "ब्रिक्स की बढ़ती प्रासंगिकता उसके व्यापारिक प्रदर्शन में भी दिखाई देती है। वर्ष 2003 में ब्रिक्स देशों का वैश्विक निर्यात लगभग 900 अरब डॉलर था, जो बढ़कर 2024 में करीब 6 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। इसी अवधि में वैश्विक निर्यात में ब्रिक्स की हिस्सेदारी लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर 24 प्रतिशत हो गई है।" उन्होंने कहा कि ब्रिक्स सहयोग उन देशों के लिए रोजगार, समृद्धि और आर्थिक अवसर पैदा करेगा जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और 40 प्रतिशत वैश्विक जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदार देशों से अपने-अपने भुगतान तंत्रों को आपस में जोड़ने, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने और डिजिटल व्यापार को वैश्विक स्तर पर अधिक सुलभ बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब इस अनुभव को ब्रिक्स देशों के साथ साझा करने का समय है। गोयल ने कहा कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) आज 11 देशों में स्वीकार किया जा रहा है और यह दुनिया के सबसे सफल डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्मों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों को अपने भुगतान नेटवर्क एक-दूसरे से जोड़ने चाहिए, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए और भविष्य की उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे सीमा-पार लेनदेन अधिक तेज, कम लागत वाले और सुविधाजनक बन सकेंगे। उन्होंने कहा, "यूपीआई पर अब प्रति वर्ष 250 अरब से अधिक लेनदेन हो रहे हैं और मात्रा के आधार पर यह दुनिया के कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन का आधे से अधिक हिस्सा दशार्ता है, जो कि भारत की डिजिटल नवाचार क्षमता और वित्तीय समावेशन की सफलता का प्रमाण है।"

पीएम मोदी के प्रयासों से मजबूत हो रहा ब्रिक्स ईरानी राष्ट्रपति ने की भारत की सराहना

नई दिल्ली, एजेंसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने शुक्रवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया अपने सबसे जटिल दौर से गुजर रही है और ऐसे समय में ब्रिक्स को संभावित सहयोग से आगे बढ़कर व्यावहारिक आर्थिक सहयोग की दिशा में काम करना होगा। अपने संबोधन की शुरूआत में पेजेश्कियन ने भारत सरकार और भारतीय जनता का बैठक की मेजबानी के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा, "मैं इस बैठक की मेजबानी के लिए भारत की मित्र सरकार और भारत के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। साथ ही ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के मूल्यवान प्रयासों की भी सराहना करता हूं।" उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र, उद्योग जगत और उद्यमियों की मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण

है क्योंकि यही लोग ब्रिक्स के भीतर सहयोग की अवधारणा को वास्तविक आर्थिक उपलब्धियों में बदल सकते हैं। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि आज दुनिया जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आर्थिक साधनों के बढ़ते इस्तेमाल जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन परिस्थितियों ने देशों के लिए आर्थिक माहौल को पहले से कहीं अधिक जटिल बना दिया है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का जवाब ब्रिक्स के पास है। उनके मुताबिक, ब्रिक्स की असली ताकत केवल सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के आकार में नहीं, बल्कि उन्हें व्यापार, निवेश और संयुक्त वित्तपोषण के मजबूत नेटवर्क में बदलने की क्षमता में निहित है। उन्होंने इसे संभावित सहयोग से परिचालन स्तर के सहयोग की ओर बढ़ने का रास्ता बताया। पेजेश्कियन ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ मुद्रा जोखिम प्रबंधन और पारस्परिक भुगतान व्यवस्था के लिए आवश्यक वित्तीय तंत्र भी विकसित किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक वित्तीय प्रणाली सीमित संख्या में मुद्राओं पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण राजनीतिक झटकों के प्रति संवेदनशील है। इसलिए व्यापारिक सहयोग को वास्तविक निवेश में बदलने के लिए ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) को सदस्य देशों में बुनियादी ढांचा और ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण का प्रमुख इंजन बनाया जाना चाहिए। ईरानी राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थानीय मुद्राओं में समर्पित क्रेडिट लाइन, स्थानीय मुद्रा में वित्तपोषण और निजी पूंजी को आकर्षित करने के लिए गारंटी तंत्र विकसित करे, ताकि सदस्य देशों के बीच निवेश और आर्थिक सहयोग को नई गति मिल सके। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच एक ऐसे मंच के रूप में आगे बढ़ना चाहिए जो सदस्य देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को अधिक मजबूत, टिकाऊ और व्यावहारिक बनाए।

राजस्थान नगरीय निकाय चुनाव

दूसरे चरण में 147 निकायों में 70.01 प्रतिशत मतदान, कोटा में सबसे कम 57.02 फीसदी वोटिंग

जयपुर, एजेंसी। राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में जमकर मतदान हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी शाम 6 बजे तक के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 147 निकायों में कुल 70.01 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। दूसरे चरण में प्रदेश के लाखों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर शहर की सरकार चुनने के लिए वोट डाला। आयोग के मुताबिक, दूसरे चरण में कुल 87 लाख 63 हजार 595 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से 61 लाख 35 हजार 153 मतदाताओं ने वोट डाला। कुल मतदान प्रतिशत 70.01 प्रतिशत रहा, जिसे काफी अच्छा माना जा रहा है। इस चरण में सबसे ज्यादा मतदान धोरीमन्ना में हुआ, जहां 91.59 प्रतिशत लोगों ने वोट डाला। वहीं, सबसे कम मतदान कोटा नगर निगम में दर्ज किया गया, जहां केवल 57.02 प्रतिशत मतदान हुआ। शहरी क्षेत्रों में कम मतदान की प्रवृत्ति इस बार भी कोटा में देखने को मिली। जिलेवार मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो अलवर में 85.22 प्रतिशत, बाड़मेर में 85.17 प्रतिशत, खैरथल-तिजारा में 88.32 प्रतिशत, फलोदी में 86.80 प्रतिशत और कोटपूतली-बहरोड़ में 86.04 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो राज्य के औसत से काफी ज्यादा है। इसी तरह अजमेर में 69.77 प्रतिशत, बालोतरा में 75.18 प्रतिशत, बांसवाड़ा में 71.36 प्रतिशत, बारां में 83.07 प्रतिशत, ब्यावर में 77.69 प्रतिशत, भरतपुर में 83.65 प्रतिशत, भीलवाड़ा में 83.88 प्रतिशत, बीकानेर में 75.09 प्रतिशत, बूंदी में 81.48 प्रतिशत, चित्तौड़गढ़ में 79.80 प्रतिशत, चूरू में 74.74 प्रतिशत, दौसा में 82.88 प्रतिशत, डीडवाना-कुचामन में 81.90 प्रतिशत, डीग में 83.04 प्रतिशत, धौलपुर में 82.06 प्रतिशत, डूंगरपुर में 71.98 प्रतिशत, श्रीगंगानगर में 75.10 प्रतिशत और हनुमानगढ़ में 80.01 प्रतिशत मतदान हुआ। जयपुर जिले में 62.88 प्रतिशत, जैसलमेर में 84.88 प्रतिशत, जालोर में 76.64 प्रतिशत, झालावाड़ में 83.19 प्रतिशत, झुंझुनूं में 77.94 प्रतिशत, जोधपुर में 71.10 प्रतिशत, करौली में 77.76 प्रतिशत, नागौर में 83.26 प्रतिशत, पाली में 70.70 प्रतिशत, प्रतापगढ़ में 81.80 प्रतिशत, राजसमंद में 79.27 प्रतिशत, सवाई माधोपुर में 74.56 प्रतिशत, सलूंबर में 78.69 प्रतिशत, सीकर में 67.81 प्रतिशत, सिरोही में 66.90 प्रतिशत, टोंक में 79.67 प्रतिशत और उदयपुर में 70.07 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। कुल मिलाकर अलवर जिला 85.22 प्रतिशत के साथ टॉप पर रहा, जबकि कोटा 57.02 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे रहा। राज्य का औसत मतदान 70.01 प्रतिशत रहा। आयोग ने बताया कि अंतिम आंकड़ों में मामूली बदलाव संभव है।

दुनिया की जीडीपी में ब्रिक्स देशों का 40 प्रतिशत योगदान, पुतिन ने दिल्ली से दिखाई वर्ल्ड को ताकत

नई दिल्ली, एजेंसी। ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन के दौरान दुनिया भर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बता दिया कि 'ब्रिक्स देशों' के सामने 'जी-7' देश कहां खड़े हैं। उन्होंने मंच से अपने शब्दों के जरिए स्पष्ट कर दिया कि "पिछले 5 सालों में, दुनिया की जीडीपी का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्से का योगदान ब्रिक्स देशों ने दिया है, जबकि तथाकथित जी7 यानी 'ग्रेट 7' देशों का योगदान इसमें सिर्फ 29 प्रतिशत रहा है।" नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंच साझा किया। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने ब्रिक्स देशों

की तारीफ करते हुए कहा, "पिछले 5 सालों में दुनिया की जीडीपी का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा ब्रिक्स देशों ने पैदा किया है, जबकि तथाकथित जी7 यानी 'ग्रेट 7' का योगदान इसमें सिर्फ 29 प्रतिशत का रहा है।" उन्होंने आगे कहा, "इस दौरान दुनिया की इकॉनमी में हुई ग्रोथ की बात करें तो हम देखते हैं कि उस ग्रोथ का आधे से ज्यादा हिस्सा ब्रिक्स देशों का रहा है, जबकि जी7 का हिस्सा इसमें सिर्फ 18 प्रतिशत रहा है। ऐसा क्यों है? जवाब आसान है, दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी ब्रिक्स देशों में रहती है, इसीलिए उनके पास बहुत ही गतिशील और जीवंत घरेलू बाजार है।" इसके बाद बोलते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, "अभी दुनिया में गहरे और बुनियादी बदलाव हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो देश 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में आर्थिक विकास में सबसे आगे थे, उनकी जगह अब विकास के नए इंजन (ब्रिक्स देश) ले रहे हैं। जब मैं 'पुराने' कहता हूं तो हम सभी समझते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। इन तथाकथित पुराने नेताओं के पास अभी भी बहुत मजबूत पक्ष और अच्छी तरह से विकसित इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीकी और वैज्ञानिक फायदे, वैज्ञानिक स्कूल आदि मौजूद हैं, लेकिन इस समय चीजों का स्वभाव ऐसा है, साथ ही मानवता और अर्थव्यवस्था का स्वभाव भी ऐसा है कि मानो दुनिया हमेशा बदल रही है।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

नई दिल्ली, एजेंसी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शुक्रवार को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए। हवाई अड्डे पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि भारत, इंडोनेशिया के साथ सहयोग, विकास और समृद्धि की साझा दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। इस बीच, थाईलैंड के उपप्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेत्केओ भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और थाईलैंड के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है। मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते एनदायिशिमिये भी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। उनका स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और अफ्रीकी संघ वैश्विक दक्षिण की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए गहन सहयोग कर रहे हैं। भारत, वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इसी क्रम में 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य देशों, साझेदार देशों और विशेष आमंत्रित देशों के नेता हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स समूह में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

भारत-चीन संबंधों में नई गर्माहट, राष्ट्रपति शी और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक की तैयारी: चीनी राजदूत

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और चीन के रिश्तों में लगातार सुधार के संकेत मिल रहे हैं। भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है कि दोनों देश राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक की तैयारी कर रहे हैं। चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "चीन और भारत, राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक की तैयारी कर रहे हैं। कजान और तियानजिन में हुई मुलाकातों के बाद, यह लगातार तीसरा साल होगा जब दोनों नेता एक-दूसरे से मिलेंगे।" शू फेइहोंग ने आगे कहा कि चीन, दोनों नेताओं के रणनीतिक निर्देशों पर अमल करने, द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नजरिए से देखने, बातचीत और सहयोग बढ़ाने, मतभेदों को सही ढंग से सुलझाने, और अच्छे पड़ोसी व एक-दूसरे की सफलता में मददगार साझेदार के तौर पर दोस्ती निभाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। बता दें कि पिछले दो सालों में दोनों नेताओं के बीच संबंधों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। 2024 में कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान और 2025 में तियानजिन में एससीओ समिट के

दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी के बीच सार्थक बातचीत हुई थी। अब तीसरे साल लगातार होने वाली यह बैठक दोनों देशों के बीच भरोसे को और मजबूत करने वाली मानी जा रही है। इससे पहले एक अन्य पोस्ट में चीनी राजदूत ने ब्रिक्स को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने लिखा था, "चीन ब्रिक्स सहयोग को महत्व देता है और इस साल सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने में भारत का समर्थन करता है।" जानकारों का मानना है कि भारत इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है और चीन का यह समर्थन कूटनीतिक लिहाज से काफी अहम है। अमेरिका के साथ टैरिफ तनाव और वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत और चीन का करीब आना वैश्विक दक्षिण के लिए एक मजबूत संदेश है।

बिहार के कटिहार में बड़ा रेल हादसा टला, टूटी हुई पटरी के ऊपर से गुजरी ट्रेन

पटना, एजेंसी। बिहार के कटिहार जिले के सेमापुर रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक बड़ा रेल हादसा टल गया, जब डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रैक के एक टूटे हुए हिस्से के ऊपर से गुजरी। माना जाता है कि ट्रेन के लोको पायलट की सतर्कता ने सैकड़ों यात्रियों के साथ होने वाले एक संभावित गंभीर हादसे को टाल दिया। ट्रेन नंबर 15904, डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के सोनपुर डिवीजन के कटिहार-बरौनी सेक्शन पर सेमापुर स्टेशन के यार्ड एरिया में घुस रही थी, तभी सुबह करीब 9 बजे उसे पटरी में एक गंभीर दरार (रेल फ्रैक्चर) का सामना करना पड़ा। इंजन और उसके ठीक पीछे वाला कोच खराब हिस्से के ऊपर से गुजर चुके थे, तभी लोको पायलट को ट्रेन के नीचे से जोरदार खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। संभावित खतरे

को भांपते हुए पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाए और ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन गार्ड और सेमापुर स्टेशन मास्टर को घटना की जानकारी दी। एक बड़ा हादसा टलने की मुख्य वजह उस समय ट्रेन की धीमी गति थी। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को सेमापुर में एक लूप या शंटिंग लाइन पर डायवर्ट किया जाना था, ताकि पीछे से आ रही राजधानी एक्सप्रेस उसे ओवरटेक कर सके। नतीजतन, स्टेशन में घुसते समय ट्रेन पहले से ही धीमी गति से चल रही थी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अगर ट्रेन अपनी सामान्य गति से चल रही होती तो टूटी हुई पटरी के कारण ट्रेन के पटरी से उतरने का बड़ा खतरा हो सकता था। खराब पटरी का पता चलते ही रेलवे अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई की। सीडब्ल्यूसीआई प्रेम प्रकाश, यूएसडी अमृत सागर और बिहपुर-सेमापुर आरपीएफ आउटपोस्ट के इंचार्ज मनोज कुमार सिंह, एक तकनीकी टीम और सुरक्षा कर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे इंजीनियरों ने शुरू में अस्थायी उपाय के तौर पर क्लैंप और फिशप्लेट लगाकर खराब हिस्से को सुरक्षित किया। जब पटरी को सुरक्षित किया जा रहा था, तब डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस लगभग दो घंटे तक उसी जगह पर खड़ी रही। अस्थायी मरम्मत पूरी होने और पटरी को आवाजाही के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ट्रेन को सीमित गति से आगे बढ़ने की अनुमति दी गई। ट्रेन के प्रभावित हिस्से को सुरक्षित रूप से पार करने के बाद, इंजीनियरिंग टीम ने रेल के टूटे हुए हिस्से की वेल्डिंग करके स्थायी मरम्मत की। घटना की पुष्टि करते हुए आरपीएफ आउटपोस्ट इंचार्ज मनोज कुमार सिंह ने कहा कि रेल में दरार या टूट-फूट देखने के बाद लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी थी। उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन ने ट्रैक को ठीक करने के लिए तेजी से कार्रवाई की और इसके बाद उस सेक्शन पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया।

बैंकों में लटके रहे ताले, हड़ताल से करोड़ों का कारोबार प्रभावित

पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर बैंककर्मियों ने किया प्रदर्शन

नावकोठी , संवाददाता, अमित कुमार

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर शुक्रवार को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बैंकों में बैंककर्मियों की एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। सुबह बैंक खुलने के निर्धारित समय पर ही कर्मचारियों ने मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इससे बैंक पहुंचे ग्राहकों को बिना काम कराए वापस लौटना पड़ा।

हड़ताल में पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया समेत अन्य बैंकों के कर्मचारी शामिल रहे। बैंक शाखाओं में नकद जमा-निकासी, चेक क्लीयरेंस, बैंक ड्राफ्ट, ऋण संबंधी कार्य तथा अन्य नियमित बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहीं। बैंक बंद रहने से व्यापारियों, पेंशनभोगियों और आम ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

बैंककर्मियों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग कार्य लागू करने की निश्चित तिथि घोषित करना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि मार्च 2024 में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह को लेकर समझौता होने के बावजूद अब तक इस संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी नहीं की गई है। बैंककर्मी शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने की मांग कर रहे हैं।

इसके अलावा पेंशन अपडेटेशन, सभी पेंशनभोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता फॉर्मूला लागू करने तथा एनपीएस से जुड़े कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में जाने का विकल्प देने की मांग भी की गई। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित मांगों पर सरकार और संबंधित पक्षों को शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए।

हड़ताल के कारण प्रखंड क्षेत्र में बैंकिंग कारोबार पर व्यापक असर पड़ा। अनुमान के मुताबिक करीब पांच करोड़ रुपये से जुड़े बैंकिंग एवं राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हुए। बैंक बंद रहने से बाजार में नकदी लेनदेन भी प्रभावित रहा। हालांकि डिजिटल माध्यमों से होने वाले भुगतान पर इसका अपेक्षाकृत कम असर पड़ा।

महिला के गले से एक लाख के सोने के जेवर छीनकर भागा बदमाश

टहलने निकली महिला को बनाया निशाना, शेखपुरा की ओर से आए युवक ने वारदात को दिया अंजाम

नावकोठी, संवाददाता, अमित कुमार

थाना क्षेत्र के हसनपुर बागर पंचायत अंतर्गत चकमुजफ्फर गांव में बुधवार की सुबह टहलने निकली एक महिला से जेवर छीनतई का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच अफरातफरी मच गई। पीड़िता ने नावकोठी थाने में आवेदन देकर अज्ञात युवक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता मृत्युंजय ठाकुर की पत्नी ने पुलिस को बताया कि वह बुधवार की सुबह गांव की मुख्य सड़क पर टहल रही थी। इसी दौरान शेखपुरा की ओर से एक अज्ञात युवक उसके पास पहुंचा और अचानक उसके गले में पहनी तीन सोने की जितिया झपटकर चकमुजफ्फर गाछी की ओर भाग निकला। महिला के अनुसार छीने गए जेवरों की अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये है। घटना के बाद पीड़िता ने शोर मचाया, लेकिन तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुका था। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष मो. फिरदौस ने बताया कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर कांड अंकित कर लिया गया है। अज्ञात बदमाश की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच की जा रही है।

समसा में भाजपा की बैठक

नावकोठी. भाजपा मंडल नावकोठी की बैठक समसा में शुक्रवार को आयोजित की गयी.बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मुकेश कुमार एवं संचालन महामंत्री अजीत सिंह ने की.इसमें सेवा संकल्प अभियान की सफलता पर विचार विमर्श किया गया.बैठक का नेतृत्व विधानसभा सह प्रभारी पवन सिंह ने किया. 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक होने वाली जन जागरुकता अभियान कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिम्मेदारी सौंपी गयी.बैठक में निवर्तमान प्रत्याशी सह राष्ट्रीय परिषद सदस्य राम शंकर पासवान, पंकज कुमार सिंह, महामंत्री दीपक कानू, मनीष सिंह, मुकेश महतो,ललन गुप्ता, अभिषेक चौहान,रानी गोस्वामी, पंकज जयसवाल,जय शंकर भारती, प्रो हरेराम सिंह, जयवर्धन सिंह, प्रभु ठाकुर आदि भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता शामिल हुए

नावकोठी : विष्णुपुर के दो विद्यालयों में तिथि भोज का आयोजन

नावकोठी, संवाददाता। प्रखंड के विष्णुपुर पंचायत अंतर्गत अपग्रेडेड मिडिल स्कूल सैदपुर विष्णुपुर में शुक्रवार को तिथि भोज का आयोजन किया गया। इसमें विद्यालय के सभी छात्र-छात्राएं सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हुए। तिथि भोज के आयोजक देवपुर निवासी विधान चंद्र भारती ने बताया कि उनकी माता जी के निधनोपरांत श्राद्ध कर्म के सभी नियम पूरे किए गए हैं। इसी उपलक्ष्य में देवपुरा अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में तिथि भोज दिया गया एवं सैदपुर अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में माता की आत्मा की शांति के लिए तिथि भोज आयोजित किया गया। भोज में कुल 444 छात्र-छात्राओं ने पूरी, सब्जी, बुनिया, रसगुल्ला, दही सहित स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लिया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक संजीत कुमार महतो, हरिहर सहनी, श्रवण कुमार, अभिलाष कुमार, चित्रलेखा कुमारी, शांति देवी, एमडीएम प्रभारी रुचिता कुमारी, बीआरसी लेखपाल कुंदन कुमार, नवनीत कुमार आदि उपस्थित थे।

पटना के जल भवन में विजिलेंस का छापा, अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार जांच के घेरे में

पटना, संवाददाता। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो (वीआईबी) की एक टीम ने शुक्रवार को पटना के जल भवन में छापेमारी की, जिससे लघु जल संसाधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया। विजिलेंस टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के तहत विभाग के ऑफिस का अचानक निरीक्षण किया। एक अधिकारी के अनुसार, यह कार्रवाई अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार के खिलाफ दर्ज मामले से जुड़ी है, जो अभी लघु जल संसाधन विभाग के छपरा जोन में तैनात हैं और मॉनिटरिंग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। लघु जल संसाधन विभाग में अधीक्षण अभियंता राजेंद्र कुमार पर अपनी ज्ञात आय के स्त्रोतों से 100 प्रतिशत से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप है। ये छापे इन्हीं आरोपों के सिलसिले में मारे गए। इस ऑपरेशन से संबंधित इलाकों में हलचल मच गई। शुरू में लोग उलझन में थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें पता चला कि छापेमारी कौन और क्यों कर रहा है। इस बीच, यह रिपोर्ट लिखे जाने के समय तलाशी अभियान जारी था और मामले के बारे में विस्तृत जानकारी आज रात बाद में मिलने की उम्मीद है। जांच के हिस्से के तौर पर विजिलेंस टीम ने अधिकारी से जुड़ी जगहों पर तलाशी शुरू की। खबरों के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि कुमार ने मुंबई के पनवेल में लगभग 75 डिसमिल जमीन खरीदी थी, जिसकी मौजूदा अनुमानित कीमत लगभग 1.75 करोड़ है। पटना में जल भवन के अलावा एसयूवी की टीमें इस मामले के सिलसिले में बिहार में चार अन्य जगहों पर भी तलाशी ले रही हैं। तलाशी के दौरान विजिलेंस टीम आय से अधिक संपत्ति का पता लगाने के लिए दस्तावेजों, संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की जानकारी की जांच कर रही है। अचानक हुई इस छापेमारी से लघु जल संसाधन विभाग में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी विजिलेंस की चल रही जांच से और जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार विजिलेंस ब्यूरो सरकारी अधिकारियों पर, खासकर ज्ञात और संदिग्ध अज्ञात स्त्रोतों से उनकी आय पर कड़ी नजर रखता है। ब्यूरो भ्रष्टाचार और ज्ञात आय के स्त्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के संदेह वाले अधिकारियों के खिलाफ नियमित रूप से छापेमारी और जांच करता है।

सीपीआई के सक्रिय सदस्य के निधन पर श्रद्धांजलि

नावकोठी.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता के निधन पर प्रखंड के हसनपुर बागर में पार्टी कार्यकताओं में शोक का माहौल है.इस सिलसिले में स्थानीय पार्टी के नेता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि पार्टी के जीवन पर्यंत सदस्य रहे शेखपुरा के 60 वर्षीय कामरेड मो रहमान का शुक्रवार को निधन हो गया.वे पार्टी के मजबूत स्तंभ थे.निधनोपरांत पार्टी के नेताओं ने उनके पैतृक आवास पर पहुंचकर पार्थिव शरीर पर पार्टी का झंडा फूल माला देकर श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर पार्टी के नसीम रब्बानी,सियाराम महतो,मो अबूल,सहदेव यादव सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे.

बिहार विधान परिषद चुनावः राजद ने 6 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान, पटना से संजीव सिंह और दिलीप कुमार को टिकट

पटना, संवाददातार। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने शुक्रवार को अपने अधिकृत प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 के लिए राजद ने 6 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। उन्होंने बताया कि दो सीटों पर अभी विचार जारी है। राजद द्वारा जारी सूची के अनुसार पटना शिक्षक सीट से डॉ. संजीव कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पटना स्नातक सीट से दिलीप कुमार राजद के प्रत्याशी होंगे। कोशी स्नातक सीट से नितेश कुमार को टिकट दिया गया है। वहीं दरभंगा स्नातक सीट से अनिल कुमार झा को मैदान में उतारा गया है। सारण शिक्षक सीट से प्रो. जयराम यादव को राजद ने उम्मीदवार बनाया है और तिरहुत स्नातक सीट से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को प्रत्याशी घोषित किया गया है। तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली राजद ने इन 6 सीटों पर अपने पत्ते खोल दिए हैं। पटना से पूर्व विधायक संजीव सिंह को एक बार फिर भरोसा जताया गया है। संजीव कुमार सिंह पिछले साल खगड़िया जिले की परबत्ता सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। इससे पहले वह परबत्ता से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (जदयू) से विधायक रह चुके हैं। बाद में उन्होंने राजद का दामन थाम लिया था। बिहार विधान परिषद की कुल 8 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनका कार्यकाल 16 नवंबर को पूरा हो रहा है। इनमें स्नातक और शिक्षक कोटे की सीटें शामिल हैं। राजद ने 6 सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं, जबकि 2 सीटों पर अभी मंथन चल रहा है। इन 8 सीटों पर चुनाव की घोषणा जल्द होने वाली है। इस बार एमएलसी चुनाव में त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। एक तरफ जदयू-भाजपा समर्थित एनडीए है तो दूसरी तरफ राजद समर्थित महागठबंधन। इसके अलावा प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी सभी 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी भी अलग-अलग सीटों पर ताल ठोक सकते हैं।

बिहार: एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी की तैयारी तेज, छह सीटों पर उम्मीदवार घोषित

पटना, संवाददाता। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए होने वाले चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने छह निर्वाचन क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि बाकी दो सीटों पर चर्चा अभी चल रही है। ये चुनाव चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की सीटों के लिए होंगे। मौजूदा एमएलसी का कार्यकाल 16 नवंबर को खत्म होने वाला है और चुनाव प्रक्रिया की घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद है। विधानसभा चुनावों के विपरीत, शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता विशेष श्रेणी के होते हैं। जहां राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को तैयार कर रहे हैं, वहीं कई निर्दलीय उम्मीदवारों के भी चुनावी मैदान में उतरने की उम्मीद है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल के कार्यालय से जारी सूची के अनुसार, पार्टी ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डॉ. संजीव कुमार सिंह और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिलीप कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नितेश कुमार, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अनिल कुमार झा, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रो. जयराम यादव और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को भी मैदान में उतारा है। आरजेडी ने कहा कि बाकी दो सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा जारी है। पार्टी द्वारा उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के बाद उनके नामों की घोषणा की जाएगी। मौजूदा एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने के करीब होने के कारण राजनीतिक दलों ने सभी आठ निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आरजेडी ने कई अहम सीटों, खासकर पटना शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपनी रणनीति पहले ही तय कर ली है। चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में से, भाजपा के प्रो. नवल किशोर यादव पटना का, कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा दरभंगा का, निर्दलीय अफाक अहमद सारण का और सीपीआई के संजय कुमार सिंह तिरहुत का प्रतिनिधित्व करते हैं। चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में, जेडीयू के नीरज कुमार पटना का, निर्दलीय सर्वेश कुमार दरभंगा का, भाजपा के एनके यादव कोसी का और निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी तिरहुत का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका कार्यकाल इस साल नवंबर में पूरा हो जाएगा। वोटरों की खास श्रेणी की वजह से उम्मीद है कि ये चुनाव आम विधानसभा चुनावों से अलग होंगे। टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी (शिक्षकों के निर्वाचन क्षेत्रों) में पटना में सबसे ज्यादा वोटर हैं, जहां 16,689 रजिस्टर्ड वोटर हैं। इसके बाद सारण में 10,800, तिरहुत में 9,204 और दरभंगा में 8,967 वोटर हैं। ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी (स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्रों) में वोटरों की संख्या काफी ज?यादा है। तिरहुत में लगभग 1.35 लाख वोटर हैं, इसके बाद कोसी में करीब 1.34 लाख, दरभंगा में लगभग 1.27 लाख और पटना में करीब 88,000 वोटर हैं। स्थापित राजनीतिक पार्टियों के साथ-साथ, निर्दलीय उम्मीदवार भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में शिक्षकों और स्नातकों के बीच प्रचार करने की तैयारी कर रहे हैं।

भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में एक दुनिया में बनाई मजबूत जगह : रामकृपाल यादव

पटना, एजेंसी। बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव ने शुक्रवार को आईएएनएस से बातचीत के दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ब्रिक्स समिट, आईएमएफ द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना, जेडीयू का नाम बदलने के प्रस्ताव और लालू परिवार पर आईआरसीटीसी मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर उन्होंने बात की। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारत को वैश्विक विकास का मुख्य इंजन बताए जाने पर उन्होंने कहा कि भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाले देशों में से एक के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि जैसे-जैसे इसकी विकास दर बढ़ रही है और वित्तीय प्रबंधन में सुधार हो रहा है, भारत ने वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्थिति बना ली है। दुनिया भर में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, भारत की वित्तीय स्थिति मजबूत हो रही है और इसकी विकास दर बढ़ रही है। इसलिए, भारत ने निश्चित रूप से दुनिया में अपनी जगह बना ली है। अगर यह कहा जा रहा है कि सभी देशों को नेतृत्व की भूमिका निभाने में भारत का समर्थन करना चाहिए, तो इसे बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात नहीं माना जा सकता। वहीं, ब्रिक्स समिट पर बोलते हुए मंत्री रामकृपाल यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सकारात्मक विजन है कि चूंकि कई बड़े देश ब्रिक्स समिट के लिए भारत आ रहे हैं, इसलिए भारत की पवित्र धरती से दुनिया में एक सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। इसके लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव और निर्णय लिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री की पहल और विजन सही है। जेडीयू का नाम बदलकर 'जनता दल नीतीश' करने के विचार पर पूछे गए सवाल पर रामकृपाल यादव ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि जेडीयू की पहचान सम्मानित नेता नीतीश कुमार से जुड़ी है। अगर पार्टी के भीतर कोई चर्चा होती है, तो पार्टी के नेता ही इस पर निर्णय लेंगे। लालू परिवार पर आईआरसीटीसी मामले में चार्ज फ्रेम होने को लेकर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ जो कोर्ट का निर्णय आया है, कानून अपना काम कर रही है। कानून जैसा समझता है, वह निर्णय लेता है।

एक नजर

पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने को लेकर यूएफबीयू ने किया हड़ताल

सहरसा, संवाददाता। शहर के सभी बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी यूएफबीयू के बैनर तले शुक्रवार को बैंक ऑफ इंडिया मुख्य शाखा के नीचे एक दिवसीय हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए एकत्र हुए। तथा सरकार की असमान पीएलआई नीति एवं पांच दिवसीय बैंकिंग के लिए आवाज बुलंद किया। इस एक दिवसीय हड़ताल तथा शनिवार, रविवार के कारण सभी बैंक कुल तीन दिनों तक बंद रहे, जिस कारण लगभग चार सौ करोड़ से ऊपर का कारोबार प्रभावित हुआ। सुबह से ही सभी बैंक कर्मी एकजुट होकर सार्वजनिक तथा निजी बैंकों को बंद कराते दिखे। मुख्य मांग 5 दिवसीय बैंकिंग को अविलंब लागू करने एवं असमान पी एल आई नीति का विरोध शामिल है। कार्यक्रम के दौरान बैंक कर्मचारी लक्ष्मण कुमार एवं मुकुंद झा ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर सभी बैंक यूनियन सभी बैंकों के सभी श्रेणी के स्टाफ अधिकारी एवं कर्मचारी संभाग के कर्मियों ने एक सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय एवं संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन प्रेषित किया गया। उन्होंने बताया कि देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी सप्ताह के 5 दिन की बैंक कार्य प्रणाली चलाए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारियों के ऊपर काम का बोझ अत्यधिक रहने के कारण उन्हें मानसिक तनाव की पीड़ा से गुजरना पड़ता है। ऐसे में सप्ताह के पांच दिवसीय कार्य पद्धति किए जाने की मांग की।

फरियादियों ने व्यवस्था और पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर खड़े किए सवाल

बक्सर, संवाददाता। बिहार सरकार एक ओर पुलिसिंग व्यवस्था को आम लोगों के घर तक पहुंचाने और थानों को जनसुलभ बनाने का दावा कर रही है, वहीं चौसा मुफस्सिल थाना में शुक्रवार को पहुंचे फरियादियों ने व्यवस्था और पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर सवाल खड़े किए। लोगों का आरोप है कि अपनी समस्याएं लेकर थाने पहुंचने पर उन्हें अपेक्षित सम्मान और सहज वातावरण नहीं मिल रहा है। विभिन्न मामलों को लेकर थाना पहुंचे लोगों ने बताया कि वहां मौजूद महिला कर्मियों और कुछ पदाधिकारियों के बातचीत करने के तरीके से वे नाराज हुए। फरियादियों का कहना था कि वे कानून का सहारा लेकर अपनी समस्या का समाधान कराने आते हैं, लेकिन कई बार व्यवहार ऐसा होता है, जिससे उन्हें लगता है कि वे गलत जगह आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने थाना अध्यक्ष की उपलब्धता को लेकर भी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि फोन करने पर अक्सर बैठक में होने की बात कही जाती है, जबकि ग्रामीण अपनी समस्या लेकर थाने पहुंचते हैं और उन्हें समुचित सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ता है। लोगों ने सुझाव दिया कि वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों को प्रतिदिन थानों की सीसीटीवी गतिविधियों की निगरानी करनी चाहिए।

भागलपुर में कोसी नदी का कहर, रेलवे लाइन बांध का 15 मीटर हिस्सा टूटा

कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ का गंभीर खतरा

भागलपुर, संवाददाता। जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत रंगरा चौक प्रखंड के बनिया इलाके में कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर और बाढ़ के तेज दबाव के कारण रेलवे लाइन बांध का करीब 15 मीटर हिस्सा टूट गया है। बांध टूटते ही बाढ़ का पानी बेहद तेज रफ्तार से गांवों की ओर बहने लगा है, जिससे आसपास के कई गांवों में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है और स्थानीय ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है।

स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, क्षेत्र में रात के समय हुई भारी बारिश और तेज आंधी के बाद कोसी नदी के जलस्तर में अचानक और अत्यधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई। नदी के उफान के कारण रेलवे लाइन बांध पर पानी का दबाव लगातार बढ़ता चला गया, जिसके परिणामस्वरूप बांध का लगभग 15 मीटर का हिस्सा अचानक जमींदोज हो गया। टूटे हुए हिस्से से पानी का सैलाब गांवों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी अब साधोपुर, मसूदनपुर, बैसी, भवानीपुर और नवगछिया-बनिया समेत आसपास के कई ग्रामीण इलाकों को अपनी चपेट में ले रहा है। पानी के इस विनाशकारी बहाव के कारण साधोपुर से बनिया को जोड़ने वाली मुख्य सड़क का भी करीब आधा हिस्सा टूटकर बह गया है, जिससे क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह प्रभावित होने की आशंका खड़ी हो गई है। रंगरा प्रखंड के मदरौनी और चापर समेत कई गांव पहले से ही बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। ऐसे में रेलवे लाइन बांध के भी टूट जाने से ग्रामीणों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं और लोग सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और संबंधित तकनीकी विभाग की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे खुद पूरे घटनाक्रम और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने प्रभावित क्षेत्र का जायजा भी लिया है।

विभाग के कर्मियों द्वारा तेज बहाव के बीच ही टूटे रेलवे लाइन बांध के रिस्टोरेशन का काम युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। हालांकि, पानी की रफ्तार अत्यधिक तेज होने की वजह से मरम्मत कार्य में भारी बाधा आ रही है। फिलहाल प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती पानी के तेज बहाव को नियंत्रित करते हुए बांध के टूटे हिस्से को जल्द से जल्द बहाल करना है, ताकि अन्य गांवों को जलमग्न होने से बचाया जा सके। प्रशासन ने आसपास के ग्रामीणों को भी सतर्क रहने की सलाह दी है।

नियोजन मेले में युवाओं को मिला रोजगार का अवसर

बक्सर, संवाददाता। जिला प्रशासन एवं जिला नियोजनालय के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को नगर भवन, बक्सर में एक दिवसीय नियोजन-सह-व्यवसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन बिहार विधानसभा के सदस्य आनंद मिश्रा, श्रम अधीक्षक एवं जिला नियोजन पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मेले में निजी क्षेत्र की 22 कंपनियों ने स्टॉल लगाकर 1000 से अधिक रिक्तियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। कुल 742 बायोडाटा प्राप्त हुए, जिनमें कंपनियों ने प्रथम स्तर पर 387 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया। एसआईएस सहित अन्य कंपनियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ऑफर लेटर भी प्रदान किए गए। राजकीय आईटीआई के स्टॉल के माध्यम से 21 युवाओं को व्यवसायिक मार्गदर्शन दिया गया। स्थानीय युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बक्सर के दो स्टार्टअप को भी अपने उत्पाद एवं गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिए स्टॉल उपलब्ध कराया गया। मुख्य अतिथि आनंद मिश्रा ने युवाओं से नियोजन मेलों में अधिक से अधिक भाग लेकर रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि करियर की शुरूआत में कार्य-कुशलता और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

सभी हितधारकों के सुझाव बिहार भवन उपविधि-2026 को अधिक प्रभावी बनायेगी: उपमुख्यमंत्री

बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप की उच्चस्तरीय समीक्षा

पटना, संवाददाता। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप की समीक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सभी हितधारकों से प्राप्त सुझाव बिहार भवन उपविधि-2026 को अधिक प्रभावी, सरल एवं जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण होंगे। इस बैठक मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार भवन उपविधि-2026 का प्रारूप पारदर्शिता, सरलता, त्वरित प्रक्रियाओं और सतत विकास के सिद्धांतों को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम एवं समयबद्ध बनाते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित और आधुनिक विकास को गति देना है। यह प्रारूप बिहार के

बदलते शहरी परिदृश्य के अनुरूप एक प्रगतिशील एवं विकासोन्मुख कदम है। नीतीश मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के विकसित बिहार के विजन के अनुरूप बिहार भवन उपविधि-2026 का प्रारूप राज्य के शहरों के सुनियोजित और सतत विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सरल एवं पारदर्शी प्रावधानों से भवन निर्माण और निवेश को गति मिलेगी तथा आधारभूत संरचना, आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। इस समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के विशेष सचिव के के पाठक, बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, विशेष सचिव नीलेश रामचन्द्र देवरे, पटना नगर निगम के आयुक्त यशपाल मीणा सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालानों का होगा त्वरित निपटारा: डीटीओ

कटिहार, संवाददाता। आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित ई-चालानों के सरल एवं त्वरित निष्पादन को लेकर जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 90 दिनों से अधिक अवधि से लंबित ई-चालानों के निस्तारण तथा 'एक मुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026' के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से विचार-विमर्श कर कार्ययोजना बनाई गई।

जिला परिवहन पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारी तथा जिले के विभिन्न परिवहन संघों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन और अधिक से अधिक चालानों के सुलहनीय समाधान को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। इसके साथ ही वाहन मालिकों और चालानधारकों को लोक अदालत की प्रक्रिया से अवगत कराने पर विशेष बल दिया गया। लंबित मामलों के निष्पादन को आसान बनाने के लिए पुलिस और परिवहन विभाग के बीच आपसी समन्वय स्थापित कर सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संघ प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया गया कि वे अपने स्तर से वाहन स्वामियों व चालकों तक इस राहत योजना की जानकारी पहुंचाएं।

उल्लेखनीय है कि लंबित ई-चालानों के समाधान के लिए 07 सितंबर से ही प्री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की कि वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहले से प्री-रजिस्ट्रेशन करा लें, ताकि 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत में बिना किसी भागदौड़ के उनके मामलों का समय पर निस्तारण हो सके।

व्यवस्था की नाकामी, बाढ़ गरीबों की नियति नहीं, भ्रष्टाचार का नतीजा: पप्पू यादव

भागलपुर, संवाददाता। जिले के खरीक प्रखंड अंतर्गत राघोपुर गांव में बाढ़ ने तबाही का भयावह मंजर पैदा कर दिया है। बाढ़ की इसी स्थिति का जायजा लेने शुक्रवार को पहुंचे पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सरकार की राहत व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े किए हैं।

शुक्रवार को राघोपुर के वार्ड नंबर 8 और 9 में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर उन्होंने उनकी पीड़ा सुनी। सांसद ने अपनी ओर से 100 से अधिक पीड़ित महिलाओं को नगद आर्थिक मदद दी। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न हादसों के शिकार परिवारों को निजी कोष से सहायता राशि भी बांटी। बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने व्यवस्था पर आक्रोश जताते हुए कहा कि खैरपुर और अतगामा के समीप बांध पर भारी संकट मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन सोया हुआ है। पीड़ितों तक बिजली, नाव, राशन और जरूरी दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं, जिससे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। इस दौरान सांसद ने लोदीपुर निवासी सिकंदर मंडल और करीब 15 दिनों से लापता बादल मंडल के परिजनों को 25-25 हजार रुपये की फौरी मदद दी। सिकंदर मंडल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जमीन बेचकर 70 लाख रुपये में बनाई गई उनकी नाव बाढ़ में डूब गई, सरकार को इसके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। खरीक के बाद सांसद गोराडीह प्रखंड के कोयली खुटाहा गांव पहुंचे, जहां हाल ही में हुए दर्दनाक नाव हादसे में पांच लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और अपनी ओर से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि 15 दिनों से लापता युवक के शव का अंतिम विदाई के लिए भी न मिलना व्यवस्था की संवेदनहीनता को दशार्ता है। सांसद ने सरकार से मांग की कि सभी मृतक परिवारों को कम से कम पांच-पांच लाख रुपये का उचित मुआवजा तुरंत दिया जाए। पप्पू यादव ने एंटी-इरोजन (कटाव निरोधी) और फ्लड फाइटिंग के नाम पर हर साल पानी की तरह बहाए जाने वाले सरकारी पैसे को लेकर बड़ा हमला बोला।

हाइवा ट्रक की चपेट में आने से महिला की मौत बेटा-बेटी सुरक्षित

सारण, संवाददाता। जिले के अमनौर थाना क्षेत्र के दुखन मोड़ के समीप एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। मृतका की पहचान डेरनी थाना क्षेत्र के विश्वंभरपुर निवासी सीमा मिश्रा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह अपने बेटा और बेटी के साथ बाइक पर सवार होकर मढ़ौरा के आवरी गांव स्थित अपने मायके जा रही थी। इसी दौरान दुखन मोड़ के पास एक 10 चक्का हाइवा ट्रेलर ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके बेटा-बेटी बाल-बाल बच गए और उन्हें हल्की चोटें आईं हैं। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष बिमलेश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया है।

मिठाई खाने से पूरा परिवार बीमार ग्राहक की शिकायत पर दुकान सील

बक्सर, संवाददाता। नगर के राजगढ़ चौक स्थित प्रजापति मिष्ठान भंडार को प्रशासन ने ग्राहक के शिकायत पर सील कर दिया । इस प्रतिष्ठान के खिलाफ प्रशासन ने स्थानीय प्रखंड के अरियांव निवासी ग्राहक व उसके परिवार के शिकायत के बाद कार्रवाई की । जिसमें उन्होंने इस दुकान की मिठाई खाने के बाद पूरे परिवार के लोगों का तबियत बिगड़ने और लगातार वोमिटिंग होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद अनुमंडलीय प्रशासन की पहल पर पीड़ित परिवार के सभी सदस्यों का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल डुमरांव में किया गया। जहां से वे स्लाइन चढ़ाने व जरूरी इलाज के बाद स्वस्थ होकर अपने घर गए । पीड़ित परिवार के प्रभावित लोगों में महिला और बच्चों की संख्या सबसे

ज्यादा थी। वहीं पुरुष सदस्य सहित लगभग 9 लोग मिठाई खाने के बाद बीमार पड़े थे। चिकित्सकों के अनुसार फूड प्वाइजनिंग के चलते लोगों की स्थिति बिगड़ी और वे बीमार हुए। इस घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडलाधिकारी राजीव कुमार, डीसीएलआर टेशलाल सिंह, थानाध्यक्ष संजय कुमार सिन्हा पुलिस बल के साथ प्रजापति मिष्ठान भंडार जाकर दुकानदार से संबंधित मामले को लेकर पूछताछ की। साथ ही मिठाई का सैंपल कलेक्ट करते हुए दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई। इस बारे में प्रभारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सिंह ने बताया की अभी इस मामले में प्रथमिकी दर्ज नहीं हुई है। वहीं उन्होंने बताया की लिए गए सैंपल को लैब में भेजा गया है। उसका रिपोर्ट आने व जांच पड़ताल के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

लम्बा संघर्ष की जीत: फिर खुली इटाढ़ी रेलवे गुमटी, बक्सर में लौटी मुस्कान

बक्सर, संवाददाता। लंबे इंतजार, आंदोलन और लगातार बढ़ते जनदबाव के बाद आखिरकार शुक्रवार को इटाढ़ी रोड स्थित ऐतिहासिक रेलवे गुमटी आम लोगों के आवागमन के लिए फिर खोल दी गई। समपार फाटक संख्या-70इ के दोबारा खुलते ही बक्सर से इटाढ़ी-दिनारा क्षेत्र की ओर जाने वाले लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। करीब तीन महीने से बंद गुमटी के कारण परेशान स्कूली बच्चों, मरीजों, किसानों, व्यवसायियों और रोजमर्रा के यात्रियों को अब लंबा चक्कर लगाने की मजबूरी से राहत मिली है।

रेलवे प्रशासन ने 30 मई 2026 को इस गुमटी को स्थायी रूप से बंद कर दिया था। इसके विकल्प के तौर पर करीब 26.40 करोड़ रुपये की लागत से रोड ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण कराया गया था। लेकिन उद्घाटन के कुछ ही दिनों बाद ओवरब्रिज के एक हिस्से में तकनीकी समस्या आने के बाद वहां से आवागमन रोक दिया गया। स्थिति यह बन गई कि एक तरफ रेलवे गुमटी बंद थी और दूसरी तरफ नया ओवरब्रिज भी लोगों के लिए उपयोगी नहीं रहा। इससे इटाढ़ी रोड और आसपास के इलाकों में आवागमन का संकट गहरा गया।

लोगों की परेशानी बढ़ी तो विरोध भी तेज होता गया। स्थानीय ग्रामीणों और विभिन्न संगठनों ने धरना-प्रदर्शन से लेकर रेल चक्का जाम तक आंदोलन किया। जनप्रतिनिधियों ने भी मामले को रेलवे के उच्च अधिकारियों और संसद तक पहुंचाया। लगातार बढ़ते दबाव और जनहित से जुड़े मामले को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने गुमटी को दोबारा खोलने की सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके बाद आवश्यक मरम्मत और तैयारियों के बाद शुक्रवार को फाटक पर आवागमन बहाल कर दिया गया। गुमटी खुलने की खबर से इटाढ़ी रोड के आसपास स्थित विद्यालयों में भी खुशी का माहौल रहा। लंबे समय से रास्ते की समस्या झेल रहे विद्यार्थियों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली।

14 को होगा हरितालिका तीज एवं मिथिला का विशिष्ट पर्व चौठचंद्र पूजा

सहरसा, संवाददाता। ब्रज किशोर ज्योतिष संस्थान एवं फाउंडेशन डॉ रहमान चौक सहरसा बिहार के संस्थापक एवं मिथिला के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित तरुण झा जी ने बताया है की मिथिला में विश्वविद्यालय पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज व्रत एवं चौरचन 14 सितम्बर को है।इस दिन भगवान गणेश की पूजा अवश्य होनी चाहिये। विघ्नहर्ता की कृपा बनी रहती है,साथ ही बताते चलें की भगवान वराह का अवतार दिवस भी इसी दिन है, भगवान वराह ने दुष्ट हिरणयाक्ष का वध किया था। हरितालिका तीज में डाली 07.28 मिनट सुबह में तृतीया तिथि में भरा जाना जाये तो सर्वश्रेष्ठ अन्यथा उदया तिथि के अनुसार सूर्यास्त तक डाली भरा जा सकता है। इस दिन सुहागिन औरतें अपने पति की लंबी आयु संतान की लम्बी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं।

निलंबित सिपाही धनंजय पासवान पहुंचे मानवाधिकार कार्यालय कहा- 'बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पर मुझे किया गया लाइन हाजिर'

एसडीपीओ ने दिया निष्पक्ष जांच का आश्वासन

भागलपुर, संवाददाता। नवगछिया पुलिस जिला में कार्यरत सिपाही धनंजय पासवान को लाइन हाजिर किए जाने का मामला अब गरमा गया है। सिपाही धनंजय पासवान ने भागलपुर स्थित 'शरन्य राष्ट्र मानवाधिकार' के कार्यालय में शुक्रवार को एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने मानवाधिकार संगठन से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और सहयोग करने की मांग की है। मानवाधिकार कार्यालय में दिए अपने आवेदन में सिपाही धनंजय पासवान ने कहा है कि उन्होंने बाढ़ आपदा के दौरान अपनी जान पर खेलकर पीड़ितों के लिए भोजन, पानी और अन्य आवश्यक सामग्रियों की

व्यवस्था की थी। वे लगातार लोगों की सेवा में जुटे हुए थे ताकि जनता के बीच पुलिस की एक बेहतर और मानवीय छवि बन सके।

सिपाही का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनकी इस बढ़ती लोकप्रियता और बेहतर छवि को बिगाड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को भ्रमित किया। सोशल मीडिया पर उनके सेवा कार्यों को गलत तरीके से पेश कर अन्य माध्यमों पर भ्रम फैलाया गया, जिसके आधार पर उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। धनंजय पासवान ने कहा, ₹जिस पुलिस पर लोग विश्वास करते हैं, ऐसी कार्रवाइयों से उनका भरोसा उठ जाएगा। मैंने केवल पुलिस विभाग का मान बढ़ाने का प्रयास किया था। मैं किसी भी प्रकार की जांच के लिए पूरी तरह तैयार हूं। सिपाही का आवेदन मिलने के बाद मानवाधिकार के अध्यक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तत्काल नवगछिया पुलिस के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से फोन पर बात की और पूरे मामले से अवगत कराया। बातचीत के दौरान नवगछिया एसडीपीओ ने मानवाधिकार अध्यक्ष को पूरा आश्वासन दिया है कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच की जाएगी। एसडीपीओ ने कहा कि यदि सिपाही धनंजय पासवान जांच में निर्दोष पाए जाते हैं, तो उन्हें पूरे सम्मान के साथ पुलिस विभाग में पुनः स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर सिपाही धनंजय पासवान के नाम से एक क्यूआर कोड पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें बाढ़ राहत के नाम पर कथित तौर पर आर्थिक सहयोग की मांग की गई थी।

एक नजर

अज्ञात वाहन की टक्कर से अनाज व्यवसायी की मौत, मचा कोहराम

सुपौल, संवाददाता। जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र में रात के सड़क हादसे में एक अनाज व्यवसायी की मौत हो गई। घटना वार्ड-2 स्थित एनएच-131 पर इंटर कॉलेज के समीप हुई। मृतक की पहचान कामेश्वर खिड़हरी (48) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, कामेश्वर खिड़हरी गुरुवार रात अपने घर के सामने एक ग्राहक का अनाज देख रहे थे। इसी दौरान राघोपुर की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों और परिजनों ने तत्काल उन्हें रेफरल अस्पताल, राघोपुर पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मधेपुरा रेफर कर दिया। परिजन उन्हें लेकर मधेपुरा जा रहे थे। इसी दौरान शुक्रवार तड़के श्यामनगर के पास रास्ते में ही कामेश्वर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन शव को लेकर करीब ढाई बजे रात घर पहुंचे। घर पहुंचते ही परिवार में मातम पसर गया। मृतक के परिवार में पत्नी चंद्रकला देवी के अलावा दो बेटे सत्यम कुमार (12) और शिवम कुमार (10) हैं। परिवार के मुखिया की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इधर, राघोपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अज्ञात वाहन और उसके चालक की पहचान करने के साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है।

लोक अदालत के लिए सुपौल न्यायमंडल में 20 पीठ गठित

ट्रैफिक चालान के लिए चार विशेष पीठ

सुपौल, संवाददाता। 12 सितंबर, शनिवार को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत के सुचारू संचालन एवं अधिकाधिक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सुपौल न्यायमंडल में कुल 20 लोक अदालत पीठों का गठन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से सिविल कोर्ट, सुपौल एवं अनुमंडलीय सिविल कोर्ट, वीरपुर में किया जाएगा।

यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निदेर्शानुसार किया जा रहा है। सुपौल न्यायमंडल में गठित पीठों के माध्यम से विभिन्न प्रकृति के समझौता योग्य मामलों का निष्पादन किया जाएगा। पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सुपौल और वीरपुर में अलग-अलग पीठों के लिए स्थान एवं आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। यह पूरी व्यवस्था प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल राजेश कुमार बच्चन के मार्गदर्शन में की गई है। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्वरित निष्पादन पर विशेष जोर दिया गया है।

सुपौल में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए कुल 16 पीठों का गठन किया गया है। इनमें 12 नियमित पीठ तथा लंबित ट्रैफिक चालान मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए चार विशेष पीठ शामिल हैं। नियमित पीठों में प्री-लिटिगेशन मामलों के साथ-साथ वैवाहिक एवं उपभोक्ता संबंधी मामले, एमएसीटी मामले, बैंक एवं वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित समझौता योग्य मामलों की सुनवाई एवं निष्पादन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के निपटारे पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। लंबित ट्रैफिक चालान मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए गठित चार विशेष पीठें टाउन हॉल, सुपौल में कार्य करेंगी। इससे ट्रैफिक चालान से संबंधित मामलों के पक्षकारों को न्यायालय परिसर में अनावश्यक भीड़ से बचाने तथा मामलों के सरल तरीके से निष्पादन में सुविधा मिलेगी।

इधर, अनुमंडलीय सिविल कोर्ट, वीरपुर में चार लोक अदालत पीठों का गठन किया गया है। इन पीठों के माध्यम से आपराधिक समझौता योग्य मामलों के अलावा बैंक, टेलीफोन बिल से संबंधित मामलों तथा अन्य समझौता योग्य मामलों का निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में पक्षकारों एवं आम नागरिकों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। न्यायालय परिसर में हेल्प डेस्क, ट्रैफिक चालान हेल्प डेस्क, स्वास्थ्य केंद्र एवं अन्य सहायता केंद्र बनाए गए हैं।

कटिहार के सभी 16 अंचलों में विशेष भूमि सर्वेक्षण तेज

कटिहार, संवाददाता। जिले के सभी 16 अंचलों में जमीन के विशेष सर्वेक्षण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रथम चरण के अंतर्गत कोढ़ा, फलका और कुसेर्ला अंचल के कुल 178 राजस्व ग्रामों में सर्वेक्षण कार्य अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इनमें से अब तक 151 राजस्व गांवों का अंतिम प्रारूप प्रकाशन (प्रपत्र-20) पूरा कर लिया गया है, जबकि 57 राजस्व ग्रामों में प्रपत्र-25 के तहत अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। वहीं दूसरी तरफ द्वितीय चरण के तहत जिले के शेष 13 अंचलों के 1336 राजस्व ग्रामों में भी सर्वेक्षण की प्रक्रिया पूरी तत्परता से जारी है। द्वितीय चरण के तहत अब तक 365 राजस्व ग्रामों में किस्तवार, 75 गांवों में खानापुरी और 17 राजस्व ग्रामों में लैंड पार्सल मैप (एलपीएम) का वितरण कार्य संपन्न हो चुका है। मौजूदा समय में बाढ़ और मानसूनी बारिश के असर को देखते हुए जिला प्रशासन शेष बचे कार्यों में तेजी लाने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार कर रहा है।

सुपौल मदरसा फूड पॉइजनिंग: इलाज के दौरान दूसरी छात्रा की भी मौत

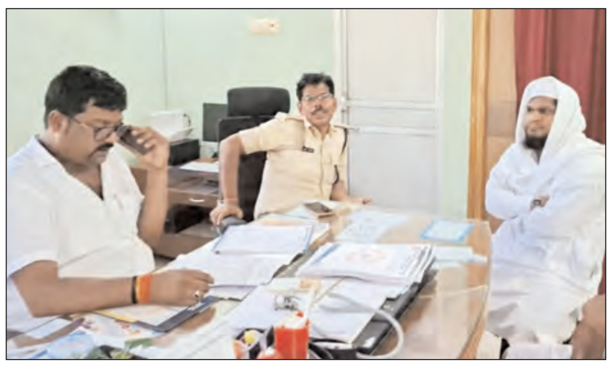

सुपौल, संवाददाता। सुपौल शहर के एक मदरसे में सोमवार को समोसा और मिठाई खाने के बाद फूड पॉइजनिंग की घटना में शुक्रवार को इलाज के दौरान एक और छात्रा की मौत हो गई। मृतका की पहचान हलीमा सादिया के रूप में हुई है। इससे पहले 10 वर्षीय अल्किशा की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी। इस घटना में अब तक दो छात्राओं की जान जा चुकी है।

जानकारी के अनुसार, सोमवार को मदरसे में रहने वाली चार छात्राओं आपिया, सहाना खातून, हलीमा सादिया और अल्किशा की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। सभी को बेहोशी की हालत में सुपौल के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इलाज के दौरान अल्किशा ने दम तोड़ दिया, जबकि शुक्रवार को हलीमा सादिया की भी हालत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। बताया गया कि अल्किशा की मां सोमवार को बच्ची से मिलने मदरसे पहुंची थीं। वह बच्ची को मिठाई और समोसा देकर गई थीं।

खाने के बाद चारों छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश हो गईं। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मदरसा संचालक खलील रहमान के अनुसार, मदरसे में करीब 60-65 छात्राएं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। संस्था लगभग दो वर्षों से संचालित है और अल्किशा भी करीब डेढ़-दो साल से यहां रह रही थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मदरसा संचालक और शिक्षकों से पूछताछ की थी। वहीं, डीएम सावन कुमार के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय की टीम ने डीपीओ समेत अधिकारियों के साथ मदरसे की जांच की।

सदर एसडीएम मनोहर कुमार साह ने बताया कि सूचना मिलने पर वे एसडीपीओ और थाना प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचे थे। जांच के दौरान मदरसे में कई बच्चियों के हॉस्टल में रहने की बात सामने आई। प्रशासन ने मदरसे को सील कर दिया है। हलीमा सादिया के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। फूड पॉइजनिंग की वास्तविक वजह और खाने की गुणवत्ता को लेकर जांच रिपोर्ट के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

भूमिहीन स्वर्ण समाज के परिवारों को भी मिले आवासीय व कृषि भूमि : संजय सिंह

दरभंगा, संवाददाता। दरभंगा जिला पूर्वी भाजपा के महामंत्री संजय सिंह ने बिहार सरकार के भू एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात कर भूमिहीन परिवारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर भूमिहीन स्वर्ण समाज के जरूरतमंद परिवारों को भी नियमानुसार आवासीय एवं कृषि भूमि उपलब्ध कराने की मांग की। संजय सिंह ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक जरूरतमंद वर्ग तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। स्वर्ण समाज में भी आर्थिक रूप से कमजोर और भूमिहीन परिवार हैं, जिन्हें आवास निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को सरकारी भूमि वितरण योजनाओं में नियमानुसार अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने मंत्री से भूमिहीन स्वर्ण परिवारों को आवासीय भूमि के साथ कृषि भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में सकारात्मक पहल करने का आग्रह किया।

बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार हर परिवार तक पहुंचेगी राहत: मंत्री

कटिहार, संवाददाता। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व सह कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री तथा कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने शुक्रवार को मनिहारी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सघन स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ के पानी से घिरे पीड़ितों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और प्रशासनिक राहत कार्यों का जायजा लिया। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और किसी भी परिवार को दाने-दाने या बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान नहीं होने दिया जाएगा। निरीक्षण के क्रम में प्रभारी मंत्री ने प्रशासन द्वारा संचालित सामुदायिक रसोइयों (कम्युनिटी किचन), मेडिकल कैंपों, पशु राहत शिविरों तथा स्वच्छ पेयजल व्यवस्था का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने सामुदायिक रसोई में तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता जांची और स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता का हाल जाना। पशु शिविरों में पशुपालकों को सूखा चारा (भूसा) और पशु चिकित्सा की नियमित सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। डॉ. प्रमोद कुमार ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जलमग्न क्षेत्रों के प्रत्येक पात्र बाढ़ प्रभावित परिवार तक त्वरित राहत सामग्री पहुंचाने और सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुग्रह राशि (जीआर) का भुगतान अविलंब पूरा करने का आदेश दिया, ताकि पीड़ितों को तत्काल आर्थिक संबल मिल सके।

पांच दिवसीय बैंकिंग समेत लंबित मांगों को लेकर बैंककर्मियों का प्रदर्शन

दरभंगा, संवाददाता। पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने, पीएलआई में भेदभाव समाप्त करने और फरवरी 2024 के द्विपक्षीय समझौते में तय मांगों को लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर बैंककर्मियों ने राष्ट्रव्यापी एकदिवसीय हड़ताल की। इसके तहत दरभंगा शहर के राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं बंद रहीं। बैंककर्मियों ने यूएफबीयू के जिला संयोजक रमण कांत मिश्रा एवं सहसंयोजक शरदंत कुमार के नेतृत्व में दरभंगा टावर पर प्रदर्शन कर सभा की। सभा को वरिष्ठ बैंकर अजीत कुमार सिंह, आनंद मोहन ठाकुर, रामाधार सिंह, प्रदीप मिश्रा, सुनील झा एवं आलम जी ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि बैंककर्मी वर्ष 2012 से पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। फरवरी 2024 में सरकार और आईबीए के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते में इसे स्वीकार किए जाने के बावजूद अब तक लागू नहीं किया गया है।

आईबीओसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज सिंह ने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी के कारण बैंककर्मी आंदोलन के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने पर 28, 29 एवं 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल तथा 26 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सभा को विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों के अलावा आईआईबीसी के जिला प्रभारी राजीव चौधरी, सीटू के नारायण झा, किसान सभा के अहमद अली तमन्ना एवं खेत मजदूर यूनियन के चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने भी संबोधित किया।

इसुआपुर में शुरू हुआ महावीरी झंडा मेला विधायक ने किया शुभारंभ

सारण, संवाददाता। भादो मास की अमावस्या के अवसर पर इसुआपुर में प्रसिद्ध महावीरी अखाड़ा सह झंडा मेला हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया। मेले का शुभारंभ तरैया विधायक जनक सिंह ने फीता काट किया। इस दौरान सुबह से ही प्रखंड मुख्यालय में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रखंड के 15 गांवों से पहुंचे लाइसेंस प्राप्त अखाड़े हाथी, घोड़े, ऊंट और पारंपरिक गाजे-बाजे के साथ इसुआपुर बाजार पहुंचे। अखाड़ों के पहुंचते ही पूरा मेला क्षेत्र गूंज उठा। मेले में युवाओं और कलाकारों ने पारंपरिक शस्त्रों के साथ अपने रण कौशल और अद्भुत करतबों का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। इसके अलावा सजे विभिन्न स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे।

एचआईवी संक्रमित पिता-पुत्र को जांच के बिना लौटाया, अधीक्षक समेत चार से जवाब-तलब

सीवान, संवाददाता। सदर अस्पताल में एचआईवी संक्रमित पिता-पुत्र को पैथोलॉजिकल जांच के लिए चार घंटे तक इंतजार कराने और बिना सैंपल लिये वापस भेजने के मामले में सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ श्रीनिवास प्रसाद ने सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ अनिल कुमार सिंह समेत चार स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है।

मामले में दो प्रयोगशाला प्रावैधिकी का वेतन तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक दिया गया है। संबंधित सभी से 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। सीएस कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, एचआईवी संक्रमित पिता-पुत्र 10 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे सदर अस्पताल स्थित एआरटी केंद्र पहुंचे थे। परामर्श के बाद दोनों को पैथोलॉजिकल जांच कराने की सलाह दी गयी। इसके बाद दोनों जांच के लिए गये, लेकिन आरोप है कि दोपहर एक बजे से शाम पांच बजे तक सैंपल लेने के लिए उन्हें बैठाये रखा गया। शाम पांच बजे के बाद बिना सैंपल लिए ही दोनों को वापस भेज दिया गया। मजबूरन दोनों मरीजों को बिना जांच कराये लौटना पड़ा। इस मामले में एआरटी केंद्र के प्रयोगशाला प्रावैधिकी अनुज कुमार तथा सदर अस्पताल के प्रयोगशाला प्रावैधिकी धर्मेंद्र कुमार और प्रमोद कुमार से जवाब मांगा गया है। सीएस ने पूछा है कि मरीजों का सैंपल नियमानुसार क्यों नहीं लिया गया और उन्हें बिना जांच कराये वापस क्यों भेज दिया गया। पत्र में इसे सरकारी कार्यों के प्रति लापरवाही बताया गया है। वहीं, सदर अस्पताल के अधीक्षक से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। पत्र में कहा गया है कि उन्हें एचआईवी संक्रमित पिता-पुत्र की जांच नहीं होने की जानकारी थी, इसके बावजूद उनकी जांच कराने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।

इसी तरह संचारी रोग पदाधिकारी-सह-जिला एड्स नियंत्रण पदाधिकारी डॉ अशोक कुमार से भी पूछा गया है कि मामले की जानकारी होने के बावजूद मरीजों की जांच कराने के लिए आवश्यक पहल क्यों नहीं की गयी। सीएस कार्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए विभाग को सूचित करने की चेतावनी दी गयी है। वहीं, दो प्रयोगशाला प्रावैधिकी का वेतन तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक अवरुद्ध कर दिया गया है। एचआईवी संक्रमित मरीजों के लिए समय पर जांच, उपचार और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। ऐसे में जांच के लिए पहुंचे पिता-पुत्र को घंटों इंतजार कराने के बाद बिना जांच लौटाये जाने की घटना ने सदर अस्पताल की व्यवस्था और एचआईवी संक्रमित मरीजों के प्रति संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिये हैं।

स्वीकृति आदेश के बाद भी आवास भत्ता भुगतान नहीं किए जाने पर शिक्षकों ने रखी डीएम के समक्ष मांग

नालंदा, संवाददाता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नालंदा जिलाध्यक्ष राजकुमार पासवान ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) प्रवीण कुमार प्रभात पर शिक्षकों को मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी नालंदा को आवेदन देकर मामले की जांच कराने तथा कार्रवाई की मांग की है। आज शुक्रवार को दिये गये आवेदन में जिलाध्यक्ष ने कहा है कि विभागीय निर्देश के आलोक में नवंबर 2025 से पात्र शिक्षकों को मकान किराया भत्ता दिया जाना था। इसके लिए नवगठित नगर पंचायत एवं नगर परिषद क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की दूरी आठ किलोमीटर के दायरे में होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग द्वारा जारी विद्यालयवार दूरी प्रमाण-पत्र के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से स्वीकृति आदेश के बाद आवास भत्ता भुगतान का प्रावधान बताया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के दूरी प्रमाण-पत्र तथा जिला शिक्षा विभाग के सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति के ही तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी आनंद विजय एवं संबंधित लिपिक भूपेन्द्र कुमार द्वारा मनमाने तरीके से शिक्षकों को आवास भत्ता का भुगतान किया गया। इस मामले को लेकर पूर्व में जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देने के साथ-साथ जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में भी शिकायत की गई है। जिलाध्यक्ष के अनुसार, मामला प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह आयुक्त, पटना प्रमंडल तथा जिला निगरानी उड़नदस्ता दल/धावा दल के स्तर पर भी विचाराधीन है।

आवेदन में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के पत्रांक-5336, दिनांक 29 अगस्त 2026 का हवाला देते हुए कहा गया है कि बिना स्पष्ट विभागीय आदेश के शिक्षकों से कार्यपालक दंडाधिकारी स्तर से निर्गत शपथ-पत्र की मांग की जा रही है। आरोप लगाया गया है कि इस प्रकार की कार्रवाई से शिक्षकों को अनावश्यक रूप से मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।राजकुमार पासवान ने जिलाधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) प्रवीण कुमार प्रभात को स्थापना संबंधी कार्य से मुक्त करने की मांग की है।

जनता दरबार में 157 फरियादियों की सुनी गई फरियाद

अररिया, संवाददाता। समाहरणालय परिसर स्थित परमान सभागार में डीएम विनोद दूहन के जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे 157 फरियादियों की फरियाद सुनी गई। जिला पदाधिकारी ने आमजनों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना तथा संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त शिकायतों एवं आवेदनों का समयबद्ध, निष्पक्ष एवं प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में ठेंगापुर, जोकीहाट निवासी मोहम्मद इसराइल ने मृतक परिजन के लिए मुआवजा भुगतान को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। वहीं जदिया, सुपौल निवासी बंधु ऋषिदेव ने सड़क दुर्घटना में पुत्र के मृत्यु के उपरांत मुआवजा राशि का भुगतान नहीं होने की शिकायत दर्ज कराई। अररिया निवासी राजेश यादव ने भूमि विवाद से संबंधित समस्या को लेकर आवेदन दिया।

खेलने निकली छह साल की लक्ष्मी की विद्युत स्पर्शाघात से मौत

दरभंगा, संवाददाता। जिले में कुशेश्वरस्थान क्षेत्र के नदी थाना क्षेत्र के विशुनिया गांव में शुक्रवार जमीन पर गिरे करंट प्रवाहित बिजली तार की चपेट में आने से छह वर्षीय बच्ची लक्ष्मी कुमारी की मौत हो गई। मृतका विशुनिया गांव निवासी स्वर्गीय रामचंद्र यादव की पुत्री थी। वह तीन भाइयों की सबसे छोटी और परिवार की इकलौती बेटी थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में मातम पसर गया।

बताया जाता है कि गुरुवार की रात तेज आंधी के दौरान बिजली पोल से तार टूटकर जमीन पर गिर गया था। रात होने के कारण किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। शुक्रवार की सुबह लक्ष्मी घर से खेलने निकली और खेलते-खेलते जमीन पर पड़े बिजली तार के संपर्क में आ गई। करंट लगने से वह मौके पर ही गिर पड़ी। परिजन उसे तत्काल कुशेश्वरस्थान अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सुबह तक जिस घर में बच्ची की चहक सुनाई दे रही थी, वहां कुछ ही देर में चीख-पुकार मच गई। सूचना मिलने पर नदी थानाध्यक्ष सुशील कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच, दरभंगा भेज दिया गया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से आंधी-तूफान के बाद टूटे तारों और क्षतिग्रस्त पोल की तत्काल जांच कराने तथा खुले में पड़े बिजली तारों को शीघ्र हटाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते बिजली आपूर्ति बंद कर तार हटाया जाता तो मासूम की जान बच सकती थी।

युवाओं को परिवर्तनकारी शक्ति मानते थे विवेकानंद

योगेश कुमार गोयल

इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं, जो केवल इतिहास नहीं बनते, बल्कि इतिहास की दिशा ही बदल देते हैं। 11 सितंबर, 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद का संबोधन ऐसा ही एक कालजयी क्षण था। आज 133 वर्ष बाद भी उस आवाज की गूंज इसलिए सुनाई देती है, क्योंकि वह किसी एक धर्म, देश या काल की आवाज नहीं थी, बल्कि समूची मानवता के लिए एकता, सहिष्णुता, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उदात्तता का उद्घोष थी।

जब युवा संन्यासी ने अपने संबोधन की शुरूआत 'मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों' कहकर की, तो सभागार में देर तक गूंजती तालियों ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मीयता की भाषा किसी अनुवाद की मोहताज नहीं होती। उस क्षण भारत अपनी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक चेतना के साथ विश्व के सामने उपस्थित था। विवेकानंद का शिकागो भाषण इसलिए असाधारण नहीं था कि उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का दावा किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने धर्म को संकीर्ण पहचान की दीवारों से बाहर निकालकर मानव-कल्याण और सार्वभौमिक बंधुत्व के धरातल पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने भारत की उस आध्यात्मिक परंपरा को सामने रखा, जो विविधता को संघर्ष नहीं, सह-अस्तित्व का आधार मानती है। उनका संदेश स्पष्ट था कि मनुष्य की अंतिम मंजिल सत्य, करुणा और आत्मबोध ही है।

आज जब दुनिया धार्मिक कट्टरता, युद्ध, असहिष्णुता और पहचान के संघर्षों से जूझ रही है, तब विवेकानंद का यह दृष्टिकोण और भी प्रासंगिक हो उठता है। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में जन्मे विवेकानंद का जीवन असाधारण जिज्ञासा, संघर्ष और आत्मान्वेषण की यात्रा था। श्रीरामकृष्ण परमहंस के सान्निध्य ने उनकी चेतना को नई दिशा दी और आगे चलकर यही नरेंद्रनाथ विश्व के लिए स्वामी विवेकानंद बन गये। उन्होंने भारत को केवल उसके अतीत के गौरव में नहीं देखा, बल्कि उसके भविष्य की संभावनाओं को भी पहचाना। वे जानते थे कि जिस देश की आत्मा जागृत हो जाये, उसे लंबे समय तक पराधीन नहीं रखा जा सकता।

इसलिए उनका सबसे बड़ा आह्वान था भारतीयों, विशेषकर युवाओं को अपनी अंतर्निहित शक्ति का बोध कराना।

विवेकानंद के लिए युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी परिवर्तनकारी शक्ति था। वे चाहते थे कि युवा भय, हीनभावना और निष्क्रियता से बाहर आएं।

उनका विश्वास था कि मनुष्य की सबसे बड़ी पराजय बाहरी परिस्थितियों से नहीं, स्वयं पर अविश्वास से होती है। इसलिए उन्होंने आत्मबल को राष्ट्र निर्माण की पहली शर्त माना। उनका प्रसिद्ध आह्वान 'उठो, जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाये' आज भी केवल प्रेरक वाक्य नहीं, बल्कि कर्म और संकल्प का घोष है। उनकी दृष्टि में शिक्षा का अर्थ केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं था। शिक्षा वह शक्ति है, जो व्यक्ति में चरित्र, विवेक, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी पैदा करे। वे ऐसे मनुष्य का निर्माण चाहते थे, जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश ला सके।

विवेकानंद के लिए राष्ट्र निर्माण का अर्थ था गरीब, वंचित और कमजोर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन देना, शिक्षा को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और युवाओं में सेवा तथा त्याग की भावना पैदा करना। विवेकानंद के चिंतन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष था आध्यात्मिकता और सेवा का समन्वय। वे उस आध्यात्मिकता के समर्थक नहीं थे, जो मनुष्य को समाज से काट दे। उनके लिए दरिद्र, पीड़ित और वंचित मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची आराधना थी। यही विचार आगे चलकर रामकृष्ण मिशन की सेवा-परंपरा का आधार बना। 1 मई, 1897 को स्थापित रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा, चिकित्सा, राहत और सामाजिक सेवा के माध्यम से उनके विचारों को व्यवहार में उतारा। 9 दिसंबर, 1898 को बेलूर मठ की स्थापना ने इस आध्यात्मिक-सामाजिक आंदोलन को स्थायी केंद्र प्रदान किया।

शिकागो के मंच पर विवेकानंद ने भारत को विश्व को देने वाली जीवंत संस्कृति के रूप में प्रस्तुत किया। उनके भाषण ने पश्चिमी दुनिया का ध्यान भारतीय दर्शन, वेदांत, योग और आध्यात्मिक चिंतन की ओर आकर्षित किया। इससे भी महत्वपूर्ण यह था कि उन्होंने भारतवासियों के भीतर आत्मगौरव जगाया। औपनिवेशिक शासन के दौर में जब भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से में हीनभावना गहरी थी, तब विदेश की धरती से एक भारतीय संन्यासी की निर्भीक आवाज ने बताया कि भारत के पास विश्व को देने के लिए बहुत कुछ है। आज का भारत आर्थिक विकास, विज्ञान, तकनीक, स्टार्टअप, अंतरिक्ष और डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में नयी ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति आर्थिक समृद्धि के बजाय उसके चरित्र, सामाजिक संवेदना, नैतिकता और नागरिक चेतना में निहित है। यही वह क्षेत्र है, जहां विवेकानंद आज भी हमारे सामने एक आईना रखते हैं।

आज के प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण वातावरण में विवेकानंद का संदेश युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वे सफलता से पहले चरित्र की बात करते हैं, अधिकार से पहले कर्तव्य की, आत्मविश्वास के साथ आत्मानुशासन की और व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ सामाजिक जिम्मेदारी की। उनका संदेश यह नहीं कि कठिनाइयां समाप्त हो जायेंगी, बल्कि यह है कि मनुष्य को इतना शक्तिशाली बनना चाहिये कि वह कठिनाइयों के सामने झुकने के बजाय उनसे संघर्ष करना सीखे। आज शिकागो से उठी वह आवाज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। वह आवाज हमें पुकार रही है कि अपने भीतर झांको, भय को परास्त करो, चरित्र गढ़ो, सेवा को जीवन का उद्देश्य बनाओ और अपनी शक्ति को मानवता के कल्याण में लगा दो।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

बाढ़ की मछलियों से खतरा

नेपाल में आयी बाढ़ का पानी जब बिहार की नदियों और जलाशयों तक पहुंचता है, तो उसके साथ केवल पानी और गाद ही नहीं आती, बल्कि अलग-अलग जलस्रोतों से बहकर मछलियां भी नये इलाकों में पहुंच जाती हैं। इस बार बिहार में ऐसी अज्ञात और असामान्य मछलियों के पहुंचने की सूचना ने एक अलग तरह की चिंता पैदा की है।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार के मत्स्य विभाग ने भी लोगों को स्पष्ट रूप से आगाह किया है कि बाढ़ के पानी के साथ नेपाल से आयी अनजान अथवा असामान्य मछलियों का सेवन न करें। यह चेतावनी महज प्रशासनिक औपचारिकता नहीं, बल्कि बाढ़ के दौरान पैदा होने वाले संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जरूरी सावधानी है। बाढ़ अपने साथ कई तरह की गंदगी और प्रदूषण लेकर चलती है। सामान्य परिस्थितियों में किसी तालाब, नदी या झील में रहने वाली मछली का जीवन एक अपेक्षाकृत नियंत्रित जलीय वातावरण में होता है। लेकिन बाढ़ के दौरान जलस्रोतों का पानी आपस में मिल जाता है और मछलियां तेज बहाव के साथ ऐसे स्थानों तक पहुंच जाती हैं, जहां पानी की स्वच्छता संदिग्ध होती है। बिहार सरकार के मत्स्य विभाग ने भी इसी आशंका को रेखांकित करते हुए बताया है कि बाढ़ में बहकर आने वाली मछलियां गंदी नालियों, मृत जानवरों और अन्य प्रदूषित पदार्थों के संपर्क में आ सकती हैं। ऐसे वातावरण में उनके जीवाणु, विषाणु या कवक से दूषित होने की संभावना बढ़ जाती है। समस्या का दूसरा पहलू यह है कि बाढ़ के समय लोगों में मछली पकड़ने और खाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी रहती है। जलस्तर बढ़ने के बाद कई मछलियां सामान्य जलस्रोतों से निकलकर खेतों, गांवों और दूसरे जलक्षेत्रों में पहुंच जाती हैं। कुछ मछलियां देखने में स्थानीय प्रजातियों से अलग हो सकती हैं और लोगों के लिए उनकी पहचान करना कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में केवल आकार, रंग या बाहरी रूप देखकर किसी मछली को खाद्य मान लेना जोखिम भरा हो सकता है। विभाग ने इसलिए बिना पहचान और संबंधित अधिकारियों की पुष्टि के किसी अपरिचित मछली को खाने योग्य नहीं मानने की सलाह दी है। यहां सरकार की चेतावनी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इस समय जिज्ञासा या लालच पर सावधानी को प्राथमिकता दी जाय। कोई मछली बड़ी है, असामान्य है या आसानी से हाथ लग रही है, इसलिए उसका सेवन करना समझदारी नहीं हो सकती। खासकर बाढ़ के पानी से पकड़ी गयी ऐसी मछलियों के मामले में बाजार में खरीद-बिक्री से भी बचने की सलाह दी गयी है। इससे न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य की रक्षा होगी, बल्कि संदिग्ध मछलियों के खाद्य श्रृंखला में शामिल होने की आशंका भी कम होगी। इस चेतावनी का एक सामाजिक पक्ष भी है। ग्रामीण और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यदि किसी व्यक्ति को असामान्य मछली दिखायी देती है, तो उसे स्वयं उसका परीक्षण या सेवन करने के बजाय स्थानीय प्रशासन अथवा जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचना देनी चाहिए। इसी तरह बाजार में भी ऐसी मछलियों की बिक्री की सूचना मिलने पर प्रशासन को जानकारी देना जरूरी है। इससे विभाग को मछलियों की पहचान करने और संभावित खतरे को समय रहते नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि इस चेतावनी को अफवाह का विषय न बनाया जाये। सरकार का उद्देश्य मछली खाने वालों में अनावश्यक भय पैदा करना नहीं, बल्कि बाढ़ के असामान्य परिस्थितिजन्य जोखिम से लोगों को बचाना है। जब तक बाढ़ का पानी सामान्य नहीं होता और जलस्रोतों की स्थिति सुरक्षित नहीं हो जाती, तब तक बाढ़ से आई अज्ञात मछलियों से दूरी रखना ही विवेकपूर्ण रास्ता है। यदि ऐसी मछली खाने के बाद उल्टी, दस्त, पेट दर्द, चक्कर या सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दें, तो तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेना चाहिए। बाढ़ पहले ही बिहार के लिए बड़ी चुनौती है। ऐसे में उससे जुड़े किसी अतिरिक्त स्वास्थ्य संकट को न्योता देना उचित नहीं। मत्स्य विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना, संदिग्ध मछलियों के सेवन और कारोबार से बचना तथा प्रशासन को सूचना देना ही फिलहाल सबसे सुरक्षित और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार है। यह सावधानी कुछ दिनों की हो सकती है, लेकिन इसके जरिये संभावित स्वास्थ्य संकट से बचाव लंबे समय तक लाभ पहुंचा सकता है।

ब्रिक्स बने सहयोग और साझेदारी का मजबूत सेतु

ललित गर्ग

नयी दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाला 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है, जब विश्व व्यवस्था गहरे संक्रमण से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का तनाव, आतंकवाद, व्यापारिक टकराव, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा की चिंता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज होती चुनौती और वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्नों ने दुनिया के सामने अनेक अनुत्तरित सवाल खड़े कर दिये हैं।

इसके साथ ही अमेरिका की व्यापार एवं रणनीतिक नीतियों से पैदा हो रहा दबाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ऐसे वातावरण में भारत की अध्यक्षता में होने वाला यह सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत ने अपनी अध्यक्षता का मूल मंत्र रखा है-लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के आधार पर भविष्य का निर्माण। ब्रिक्स अब 2006 में आरंभ हुई उस मूल अवधारणा से बहुत आगे निकल चुका है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आये थे और बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ। विस्तार के बाद यह 11 सदस्यीय समूह बन चुका है और इसका प्रभाव वैश्विक दक्षिण की राजनीति और अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2026 ब्रिक्स की स्थापना के दो दशक पूरे होने का वर्ष भी है। भारत के लिए यह अध्यक्षता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह ब्रिक्स को किसी पश्चिम-विरोधी या अमेरिका-विरोधी मंच के रूप में नहीं, बल्कि विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रचनात्मक, संतुलित और बहुपक्षीय आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है। ब्राजील में 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने, बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार वैश्विक शासन, जलवायु वित्त, स्वास्थ्य, व्यापार और वित्तीय सहयोग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी। रियो घोषणा में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया था। साथ ही स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय लेन-देन, सीमा-पार भुगतान व्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही गयी थी। भारत को 2026 की अध्यक्षता सौंपते हुए ब्राजील ने नयी दिल्ली से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की थी। इस दृष्टि से दिल्ली सम्मेलन की पहली बड़ी कसौटी यही होगी कि ब्रिक्स घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच की दूरी कितनी कम कर पाता है। भारत ने अध्यक्षता के दौरान 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किये हैं। राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं जन-जन संपर्क-इन तीनों क्षेत्रों में व्यावहारिक परिणामों पर जोर दिया गया है। इसलिए अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि सम्मेलन के अंत में केवल लंबा संयुक्त घोषणापत्र सामने आता है या कुछ ऐसे ठोस फैसले भी होते हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में दिखाई दे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। एआई ने चिकित्सा, शिक्षा, कृषि, उद्योग, वित्त और शासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं खोली हैं, लेकिन इसके साथ रोजगार, डेटा सुरक्षा, गलत सूचना, साइबर सुरक्षा और तकनीकी असमानता के खतरे भी बढ़े हैं। ब्राजील सम्मेलन में भी एआई के वैश्विक शासन को लेकर व्यापक चिंता व्यक्त की गयी थी। भारत अब ब्रिक्स देशों के बीच एआई, उन्नत कंप्यूटिंग, क्वांटम तकनीक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में जोर दे रहा है।

यदि ब्रिक्स तकनीक को कुछ शक्तिशाली देशों और कंपनियों के नियंत्रण से बाहर निकालकर विकासशील देशों की पहुंच तक ले जाने की प्रभावी व्यवस्था बना सके, तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक है। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का वजन बढ़ रहा है, लेकिन समूह के भीतर आपसी व्यापार अभी भी उसकी संभावित क्षमता के अनुरूप नहीं है। भारत आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत और विविध बनाने, छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने तथा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जयपुर में हुई ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स इकोनोमिक पार्टनरशिप 2030, एमएसएमई के लिए वित्तीय सुविधा और अधिक संतुलित व्यापार जैसे मुद्दों पर प्रगति हुई है। यहां 'डी-डॉलराइजेशन' का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत का दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक है। भारत किसी नई साझा ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण की जल्दबाजी में नहीं है। इसके बजाय सीमा-पार डिजिटल भुगतान की ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर है, जिससे सदस्य देश अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में अपेक्षाकृत सुगम व्यापार कर सकें। यह दृष्टिकोण अमेरिकी डॉलर के खिलाफ किसी राजनीतिक मोर्चेबंदी से अधिक वित्तीय स्वायत्तता और लेन-देन की सुविधा का प्रयास है। परंतु ब्रिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंतरिक विविधता और मतभेद हैं। भारत और चीन के बीच सीमा एवं रणनीतिक अविश्वास की विरासत अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। रूस और पश्चिम के बीच संघर्ष, ईरान से जुड़े तनाव तथा पश्चिम एशिया की जटिल परिस्थितियां भी ब्रिक्स के लिए साझा राजनीतिक रुख बनाना कठिन बनाती हैं। विशेष रूप से पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट में ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के अलग-अलग हित हैं। ऐसे में ब्रिक्स यदि हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाता तो यह उसकी सीमाओं को उजागर करेगा।

यही कारण है कि भारत के सामने इस सम्मेलन में सबसे कठिन कूटनीतिक संतुलन है। उसे चीन और रूस के साथ सहयोग भी बढ़ाना है, लेकिन अमेरिका और यूरोप सहित पश्चिमी देशों से अपने आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध भी बनाये रखने हैं। भारत का हित किसी एक शक्ति-ध्रुव के साथ खड़े होने में नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत करने में है। ब्रिक्स को यदि केवल 'पश्चिम के विकल्प' के रूप में प्रस्तुत किया गया तो उसकी स्वीकार्यता सीमित हो सकती है, लेकिन यदि वह वैश्विक दक्षिण के विकास, शांति, तकनीकी समानता और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व का मंच बनता है, तो उसका महत्व कहीं अधिक बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उनका तर्क है कि बीसवीं सदी में बनायीं गयी संस्थाओं को इक्कीसवीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप बदलना होगा। आज विश्व अर्थव्यवस्था में जिन देशों का योगदान बढ़ा है, यदि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो संस्थाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता दोनों प्रभावित होती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग इसी व्यापक संदर्भ का हिस्सा है। ब्रिक्स इस मांग को संगठित आवाज देने का प्रभावी माध्यम बन सकता है। लेकिन सम्मेलन की सफलता का वास्तविक पैमाना अमेरिका की आलोचना या पश्चिमी व्यवस्था को चुनौती देना नहीं होगा। सफलता तब मानी जायेगी जब ब्रिक्स दुनिया को बेहतर विकल्प दे-ऐसा विकल्प जिसमें आर्थिक सहयोग हो, तकनीकी साझेदारी हो, ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा हो, आतंकवाद के विरुद्ध साझा प्रतिबद्धता हो, आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा हो, पर्यावरणीय संतुलन हो और विकासशील देशों की वास्तविक भागीदारी हो। भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना तभी सार्थक होगी, जब ब्रिक्स शक्ति-संघर्ष का नया अखाड़ा बनने के बजाय सहयोग का नया सेतु बने। अंततः दिल्ली सम्मेलन भारत की कूटनीतिक क्षमता की भी परीक्षा है और ब्रिक्स की प्रासंगिकता की भी। दुनिया आज युद्ध से अधिक शांति, प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग और प्रभुत्व से अधिक साझेदारी चाहती है। मानवता का भविष्य केवल हथियारों, अंतरिक्ष अभियानों या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति में नहीं, बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के बीच विश्वास, सह-अस्तित्व और साझा विकास में सुरक्षित है। यदि नई दिल्ली सम्मेलन घोषणाओं से आगे बढ़कर इस विश्वास को संस्थागत रूप देने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठा सका, तो यह भारत की अध्यक्षता की बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा ब्रिक्स भी अनेक वैश्विक मंचों की तरह उम्मीदें जगाने वाला, लेकिन अपेक्षाओं पर अधूरा उतरने वाला संगठन बनकर रह जायेगा।

सनातन और विकास की राह पर नया उत्तर प्रदेश

मृत्युंजय दीक्षित

[illegible]

[illegible]

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

विकास वार्ता (दैनिक) ई-पेपर प्रकाशक एवं संपादक : राजकिशोर सिंह, विकास विद्यालय शिक्षकनगर डुमरी बेगूसराय बिहार 85117, मुद्रक: सोमेश कुमार चौधरी, दामोदरपुर पासोपुर बेगूसराय बिहार - 851112, मुद्रणालय - जागो गांव, जागो प्राइवेट आईटीआई, दामादरपुर बेगूसराय-851112, RNI NO-BHHin/5/A044

कालीघाट में मछली का भोग खाकर शुभेंदु अधिकारी ने बागेश्वर बाबा का किया बचाव

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कालीघाट स्थित काली मंदिर में मछली का भोग ग्रहण कर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के मांसाहारी भोजन संबंधी बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि किसी संत ने अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की है। जिसे स्वीकार करना है, वह स्वीकार करेगा और जिसे नहीं करना है, वह नहीं करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भवानीपुर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर जलाकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कौशिकी अमावस्या के अवसर पर गुरुवार शाम कालीघाट मंदिर पहुंचे और मां काली की पूजा-अर्चना की। पूजा के बाद उन्होंने

मंदिर परिसर में जमीन पर बैठकर भोग ग्रहण किया। भोग में मछली का सिर, तली हुई मछली और बासंती पुलाव शामिल था। मुख्यमंत्री के मछली का भोग ग्रहण करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुईं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के उस बयान के बारे में पूछे जाने पर, जिसमें उन्होंने दुर्गापूजा के दौरान बंगालियों से मछली और मांस का सेवन नहीं करने की अपील की थी, मुख्यमंत्री ने कहा, हृएक संत ने अपनी राय व्यक्त की है। जो इसे मानना चाहते हैं, वे मानेंगे और जो नहीं मानना चाहते, वे नहीं मानेंगे ह्रू

शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वह सनातनी हिंदू हैं और अलग-अलग धार्मिक अवसरों पर अपनी परंपरा के अनुसार आहार ग्रहण करते हैं। उन्होंने कहा, ह्रमहाष्टमी के दिन जब मैं मां दुर्गा की पूजा करता हूं, तब सात्विक भोजन करता हूं। कार्तिक महीने में भी सात्विक भोजन करता हूं। वहीं मां काली को चढ़ाए जाने वाले बकरे के मांस का भी सेवन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीघाट मंदिर में मां काली को जो भोग चढ़ाया गया, उसमें मछली का सिर, तली हुई मछली और बासंती पुलाव था और उन्होंने वही भोग ग्रहण किया। कालीघाट मंदिर की धार्मिक परंपरा में देवी को मछली और मांस सहित विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। बंगाल में धार्मिक आस्था और खान-पान की परंपराएं लंबे समय से एक-दूसरे के साथ जुड़ी रही हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मांसाहारी भोजन के खिलाफ अपील के बाद राज्य के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए थे। आलोचकों ने आरोप लगाया कि उनके बयान से बंगाली खान-पान और सांस्कृतिक परंपराओं पर सवाल खड़े हुए हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने विरोध प्रदर्शन के तरीके को लेकर कड़ा रुख अपनाया। इससे पहले गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने भवानीपुर थाने के सामने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर जलाकर प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया।

बागेश्वर धाम प्रमुख की तस्वीर जलाने के आरोप में कांग्रेस नेता गिरफ्तार

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की विधानसभा में दी गई चेतावनी के अगले ही दिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर जलाने के आरोप में कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया। भवानीपुर थाने की पुलिस ने दक्षिण कोलकाता जिला कांग्रेस के महासचिव अतनु दास को शुक्रवार तड़के टॉलीगंज स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस महीने की शुरुआत में कोलकाता आए । इस दौरान उन्होंने दुर्गापूजा के दौरान मांसाहारी भोजन करने को लेकर टिप्पणी की थी। उनके बयान को लेकर राज्यभर में विवाद खड़ा हो गया । यहां तक कि भाजपा के कई नेताओं ने भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की टिप्पणी से असहमति जताई। इसी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने भवानीपुर थाने के सामने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की तस्वीर जलाकर प्रदर्शन किया था। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अतनु दास ने किया था। तस्वीर जलाने की घटना पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कड़ा रुख अपनाया। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने इस मामले का उल्लेख करते हुए कोलकाता पुलिस आयुक्त को संबंधित लोगों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा था, मैंने भवानीपुर थाने के सामने कुछ लोगों को तस्वीर जलाते देखा है।

एक नजर

कंडा पैक्स में 13.87 लाख के धान घोटाले का खुलासा, कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार

पलामू, एजेंसी। पलामू जिले के नावाबाजार प्रखंड के कंडा पैक्स में धान खरीद के नाम पर करीब 13.87 लाख रुपये के घोटाले का मामला सामने आया है। पुलिस अनुसंधान में धान खरीद से जुड़ी गड़बड़ी का मुख्य आरोपित पैक्स का कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता सामने आया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, कंप्यूटर ऑपरेटर ने कथित तौर पर फर्जी आईडी बनाकर धान की खरीद दिखाई और उसका भुगतान दूसरे खातों में कराया। जांच में यह भी सामने आया है कि फर्जी तरीके से किए गए भुगतान में राहुल की पत्नी और मां के बैंक खातों का भी इस्तेमाल किया गया। कंडा पैक्स के माध्यम से करीब छह हजार क्विंटल धान की खरीद दिखाई गई थी। पहले चरण में सरकार की ओर से करीब चार हजार क्विंटल धान का भुगतान भी किया जा चुका था। इसके बाद किसानों ने अपनी बकाया राशि के भुगतान के लिए पैक्स पर दबाव बनाना शुरू किया। इसी दौरान धान खरीद और स्टॉक की जांच की गई तो कथित अनियमितताओं का खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि कागजों पर करीब छह हजार क्विंटल धान की खरीद दर्ज है, जबकि पैक्स के पास करीब 5,500 क्विंटल धान का ही हिसाब उपलब्ध है। करीब 500 क्विंटल धान फर्जी आईडी के माध्यम से खरीदा हुआ दिखाया गया, लेकिन यह धान पैक्स के गोदाम तक पहुंचा ही नहीं। इसके बावजूद करीब 13.87 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया। धान खरीद में गड़बड़ी सामने आने के बाद कंडा पैक्स अध्यक्ष प्रभुनारायण सिंह ने नावाबाजार थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। अनुसंधान के दौरान पुलिस को फर्जी आईडी, भुगतान और धान के स्टॉक में अंतर से जुड़े कई तथ्य मिले। नावाबाजार थाना प्रभारी संजय कुमार यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कंप्यूटर ऑपरेटर राहुल गुप्ता और उसके एक दोस्त की भूमिका सामने आई है। दोनों को मामले का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। राहुल गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पूरे मामले की जांच अभी जारी है।

ममता बनर्जी की श्रीरामपुर सभा पर हाई कोर्ट की रोक

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हुगली के श्रीरामपुर में प्रस्तावित टीएमसी सभा पर कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी। राज्य सरकार की अपील के बाद टीएमसी की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पार्टी 11 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए तैयार है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभा पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की। खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश के साथ न्यायमूर्ति तपाब्रत चक्रवर्ती भी शामिल हैं। अदालत ने यह आदेश राज्य सरकार और उस जमीन के मालिक की ओर से दायर अपील पर दिया, जिसमें एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत शुक्रवार को श्रीरामपुर के महेश जगन्नाथ देव स्नानपीठ मैदान में सभा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। गुरुवार को ही न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने शुक्रवार दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक सभा आयोजित करने की अनुमति दी थी। अदालत ने अधिकतम 2,000 लोगों के शामिल होने की शर्त रखी थी। इससे पहले टीएमसी की ओर से जीटी रोड से जुलूस निकालने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन पुलिस ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इसके खिलाफ पूर्व टीएमसी विधायक असीत मजूमदार ने हाई कोर्ट का रुख किया था।

अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड, एक गिरफ्तार

दुमका, संवाददाता। जिले के हंसडीहा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। गिरफ्तार आरोपित का नाम अक्षय कुमार है। पुलिस छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई रामगढ़ मोड़ स्थित रेलवे ओवरब्रिज के समीप संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री से की।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार निर्माण में प्रयुक्त 55 प्रकार मशीनें और अन्य उपकरण बरामद कर फैक्ट्री को सील कर दिया। इसकी जानकारी गुरुवार को प्रेसवार्ता कर थाना प्रभारी अजीत कुमार ने दिया। उन्होंने बताया कि करीब दो माह से अवैध मिनी गन फैक्ट्री चल रहा था। मामले में छापेमारी कर विभिन्न समाग्री जब्त करते हुए पांच नामजद को आरोपित बनाया गया है। जिसमे से एक नामजद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, कुछ

दिन पूर्व कोलकाता एसटीएफ ने दो हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में तस्करों ने खुलासा किया कि हंसडीहा में अवैध रूप से पिस्टल और देशी तमंचों का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद कोलकाता एसटीएफ ने झारखंड पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दुमका पुलिस सक्रिय हुई और संदिग्ध मकान की चारों ओर से घेराबंदी कर छापेमारी की। पुलिस जब मकान के अंदर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मकान के भीतर हथियार निर्माण का पूरा सेटअप तैयार था। मौके से लेथ मशीन समेत कई ऐसे उपकरण बरामद किए गए जिनका उपयोग अवैध हथियार बनाने में किया जाता था। मौके पर एसपी पीतांबर सिंह खेरवार देर शाम हंसडीहा पहुंच बरामद मिनी गन फैक्ट्री का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान हंसडीहा सर्किल इंस्पेक्टर प्रियंका आनंद, थाना प्रभारी अजीत यादव, सरैयाहाट थाना प्रभारी अनुज कुमार, रामगढ़ थाना प्रभारी मनोज कुमार, जामा थाना प्रभारी अजीत कुमार तथा कोलकाता एसटीएफ की टीम मौजूद रही।

पश्चिम मेदिनीपुर में सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ा भरोसा, तीन हजार परिवारों ने किया आवेदन

मेदिनीपुर, एजेंसी। बिजली का खर्च कम करने के लिए पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बड़ी संख्या में परिवार घरों की छत पर सौर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन की ओर रुख कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिले में 'प्रधानमंत्री सूर्य घर' योजना को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हुई हैं।

जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, अब तक करीब तीन हजार परिवारों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। घर में सौर ऊर्जा का उत्पादन कर बिजली बिल का बोझ कम करना इस योजना का प्रमुख आकर्षण बना हुआ है।

प्रशासन की ओर से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में योजना को लेकर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि घर की छत पर सौर पैनल लगाकर उत्पादित बिजली का उपयोग करने से मासिक बिजली खर्च में बचत की जा सकती है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिमाह 100 यूनिट से कम

बिजली का उपयोग करने वाले परिवार एक से दो किलोवाट क्षमता के सौर पैनल लगा सकते हैं। इसकी अनुमानित लागत 70 हजार से एक लाख 40 हजार रुपये तक हो सकती है। इस पर करीब 30 से 60 हजार रुपये तक सरकारी अनुदान मिलने का प्रावधान है।

वहीं, 200 से 300 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए दो से तीन किलोवाट क्षमता के सौर पैनल की आवश्यकता हो सकती है। इसकी लागत करीब दो लाख रुपये तक हो सकती है और सरकारी अनुदान 60 से 70 हजार रुपये तक मिलने की बात बताई गई है।

इसके अलावा, प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करने वाले परिवारों के लिए तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के सौर पैनल लगाने की व्यवस्था है। इस श्रेणी में अधिकतम 78 हजार रुपये तक सरकारी अनुदान मिलने का प्रावधान बताया गया है। जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले 'पीएम सूर्य घर' पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद संबंधित प्रशासन और बिजली विभाग की ओर से आवेदन की जांच की जाएगी। सौर पैनल लगने के बाद मीटर लगाने और नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

झारखंड में जल्द बनेगी महिला किसान खुशहाली योजना : शिल्पी तिर्की

रांची, एजेंसी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि महिला किसान खुशहाली योजना राज्य की महिला किसानों के लिए फ्लैगशिप योजना बनने जा रही है। विभिन्न संस्थाओं, विशेषज्ञों और महिला किसानों से मिले सुझावों के आधार पर समेकित खेती को केंद्र में रखकर योजना तैयार की जा रही है। विभागीय स्तर पर सभी तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं को अंतिम रूप देने के बाद इसे जल्द मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री शिल्पी तिर्की गुरुवार को नेपाल हाउस स्थित सभागार में कृषि विभाग की प्रस्तावित महिला किसान खुशहाली योजना को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में बोल रही थी। बैठक में योजना के स्वरूप, लाभार्थी चयन, समेकित खेती मॉडल, सरकारी सहायता और लाभुक अंशदान पर विस्तार से चर्चा हुई।

सड़क हादसे में पिता-पुत्री की मौत से भड़का आक्रोश, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम

पूर्वी सिंहभूम, एजेंसी। घाटशिला के अमाइनगर पुलिया के पास सड़क हादसे में पांच वर्षीय बच्ची और उसके पिता की मौत के बाद गुरुवार को परिजनों एवं ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर उतर आया। गोपालपुर फाटक के समीप लोगों ने सड़क जाम कर आवागमन ठप कर दिया। करीब दो घंटे तक चले जाम से घाटशिला-मुसाबनी, मोहंदरा सहित आसपास के मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। गोपालपुर सहित आसपास के गांवों के बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए।

बताया गया कि 02 सितंबर की रात सुवर्णरेखा नदी का बढ़ा जलस्तर देखने के लिए सुब्रतो सिन्हा अपने परिवार के साथ अमाइनगर पुलिया पहुंचे थे। इसी दौरान तेज

रफ्तार और अनियंत्रित कार संख्या जेएच05डीके-0236 ने पुलिया के पास खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में सुब्रतो सिन्हा (42), उनकी पत्नी सुष्मिता सिन्हा, पांच वर्षीय बेटी श्रेया कृष्णा सिन्हा और दो वर्षीय चांद सिन्हा घायल हुए थे। इलाज के दौरान करीब चार दिन पहले श्रेया की मौत हो गई थी। बुधवार को बेहतर इलाज के लिए सुब्रतो को जमशेदपुर से कोलकाता ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के पिता-पुत्री की मौत से इलाके में शोक के साथ आक्रोश फैल गया।

प्रदर्शनकारियों ने घाटशिला में नशामुक्ति केंद्र खोलने, तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई, परिवार के एक सदस्य को झारखंड राज्य आजीविका मिशन में नौकरी और दुर्घटना के जिम्मेदार पक्ष से 50 लाख रुपये मुआवजा दिलाने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि नशे और तेज रफ्तार के कारण क्षेत्र में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं।

सूचना पर घाटशिला थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार मुंडा और अंचल अधिकारी निशांत अमर मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी ने बताया कि हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हुई है। मामले में एक आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपित फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।

पांच दिवसीय बैंकिंग की मांग को लेकर आज बैंक हड़ताल

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर देशभर में बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं। बैंकिंग क्षेत्र के यूनियनों की ओर से सरकार पर पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन के उपाध्यक्ष सुभ्रज्योति चटर्जी ने कहा कि शुक्रवार की बैंक हड़ताल का मुख्य मुद्दा पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना है। उन्होंने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस मुद्दे को लेकर पहले ही 28, 29 और 30 सितंबर को तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा कर रखी है।

उन्होंने कहा कि यदि सरकार की ओर से इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया तो 26 अक्टूबर से लगातार हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी गई है। उनके अनुसार बैंक यूनियनों की कई अन्य मांगें भी हैं, लेकिन इस समय पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था लागू करना सबसे प्रमुख मांग है।

सुभ्रज्योति चटर्जी ने दावा किया कि पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था के प्रस्ताव को सरकार पहले ही स्वीकार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि 2024 में हुए द्विपक्षीय समझौते और बैंकिंग उद्योग के वेतन संशोधन समझौते के दौरान पांच दिवसीय बैंकिंग को लेकर सहमति बनी थी। इसके बावजूद अब तक इसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया है।

बैंक अधिकारियों का कहना है कि सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग व्यवस्था लागू होने से बैंक कर्मचारियों को शनिवार और रविवार को अवकाश मिलेगा। यूनियनों का तर्क है कि इससे कर्मचारियों के कार्य-जीवन संतुलन में सुधार होगा, जबकि ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से लगातार बैंकिंग सुविधाएं मिलती रहेंगी।

बैंक यूनियनों ने सरकार से पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था को लागू करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि मांग पर सकारात्मक फैसला नहीं होने पर आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से और व्यापक किया जाएगा।

त्योहारों को लेकर प्रशासन अलर्ट, पंडाल से लेकर विसर्जन तक सुरक्षा के कड़े निर्देश

रांची, एजेंसी। आगामी त्योहारों को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में बैठक की। बैठक में पुलिस और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा की गई।

राजधानी रांची में आने वाले गणेश चतुर्थी, करम पर्व, दुर्गापूजा, दीपावली, छठ और काली पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। त्योहारों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ लोगों की सुरक्षा, ट्रैफिक, साफ-सफाई और विसर्जन व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने कई अहम निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने पूजा समितियों को पंडाल निर्माण में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा। पंडाल में आने-जाने के लिए

पर्याप्त रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट, सुरक्षित बिजली वायरिंग और अग्निशमन उपकरण की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने का निर्देश दिया गया।

प्रशासन ने यह भी साफ कर दिया कि पंडाल या तोरण द्वार को बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर या किसी अन्य विद्युत संरचना से सटाकर नहीं बनाया जाएगा। बिजली विभाग को पूजा पंडालों का नियमित निरीक्षण करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पूजा प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर भी प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई है। समितियों को तय किए गए विसर्जन मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा। विसर्जन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की एमवीआई जांच, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की जांच और नो-एल्कोहल टेस्ट के बाद ही वाहन को विसर्जन में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए पूजा समितियों से अंडरटेकिंग भी लेने को कहा गया है। करम पर्व के दौरान तालाबों और पूजा स्थलों पर भीड़ को देखते हुए नगर निगम को साफ-सफाई, रोशनी और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर क्रेन की व्यवस्था भी रखने का निर्देश दिया गया।

छठ पर्व को लेकर सभी घाटों की समय पर सफाई, पर्याप्त लाइटिंग, सुरक्षित रास्ते और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। ज्यादा भीड़ वाले घाटों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

सरकार ने हाईकोर्ट को बताया- रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार के लिए प्रसाद योजना से मांगा जाएगा फंड

रांची, एजेंसी। रामगढ़ स्थित रजरप्पा मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर केंद्र सरकार की प्रसाद स्कीम से फंड मांगा जाएगा। इसकी जानकारी गुरुवार को न्यायालय को सरकार की ओर से दी गई। जिसपर न्यायालय ने मौखिक कहा कि जब केंद्र सरकार से ही फंड मांगना था तो इतनी जल्द वहां के 254 दुकानदारों को क्यों हटाया गया। न्यायालय ने कहा कि पूर्व में पर्यटन सचिव की ओर से कहा गया था कि इसके लिए फंड की कमी नहीं है। आज सरकार दूसरी बात कह रही है। डीपीआर बनाने में भी काफी समय लग रहा है।

न्यायालय ने मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए, मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर निर्धारित की। सुनवाई के दौरान डीसी रामगढ़ कोर्ट में हाजिर हुए। प्रार्थी संजीव कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता भरत कुमार ने पक्ष रखा।

पिछली सुनवाई में न्यायालय को बताया गया था कि रामगढ़ स्थित रजरप्पा मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 102 करोड़ की राशि के डीपीआर की तकनीकी स्वीकृति राज्य सरकार ने दे दी है। अब प्रशासनिक स्वीकृति टूरिज्म विभाग को देना है। न्यायालय ने मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर से हटाए गए 254 वेंडरों को जल्द अस्थाई दुकान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था।

उच्च न्यायालय ने पूर्व की सुनवाई में कहा था कि वर्ष 2023 में एक जनहित याचिका में मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के संदर्भ में आदेश पारित किए थे। मां छिन्नमस्तिका मंदिर के निकट स्थित भैरवी नदी तट पर सुरक्षा के अभाव में कई लोगों की मौत हो रही है। ऐसे में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन जरूरी है ताकि वहां सुरक्षा व्यवस्था और पर्यटकों को बेहतर सुविधा मिल सके।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने संजीव कुमार सिंह ने अवमानना याचिका दाखिल कर झारखंड उच्च न्यायालय की ओर से एक जनहित याचिका में 11.08.2023 परित आदेश का अनुपालन कराने का आग्रह किया है। परित आदेश में उच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य, पर्यटन विभाग, झारखंड पर्यटन विकास निगम और रामगढ़ जिला प्रशासन को दस अनिवार्य निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, स्थायी स्नान घाटों का निर्माण, वस्त्र बदलने के कक्ष, शौचालयों की व्यवस्था, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सीय सुविधाएं सुनिश्चित करना, अतिक्रमण हटाना, नदी का चौड़ीकरण आदि शामिल हैं।

खदान में मिला महिला का कंकाल, इलाके में फैली सनसनी

धनबाद, एजेंसी। धनबाद के बलियापुर प्रखंड के बाघमारा पंचायत अंतर्गत हरिहरटांड़-टेका खुदु जंगल स्थित एक खदान में गुरुवार को महिला का कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कंकाल मिलने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने इसकी सूचना बलियापुर थाना पुलिस को दी। इसके बाद थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खदान से कंकाल को बरामद किया। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया कंकाल करीब 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला का प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने अनुमान जताया है कि कंकाल करीब दो महीने पुराना हो सकता है। कंकाल के साथ साड़ी भी मिली है, जिससे उसके महिला का होने की पुष्टि हुई है। हालांकि, अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है।

एक नजर

पाक में क्वालिटी है, युवा खिलाड़ियों पर बहुत जल्द कोई धारणा नहीं बना सकतेः माइकल स्मिथ

बर्मिंघम, एजेंसी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। शुरूआती 2 मैच हारकर पहले ही सीरीज गंवा चुकी पाकिस्तान की स्थिति बर्मिंघम में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में भी चिंताजनक है। सीरीज में पाकिस्तान के सीनियर और जूनियर दोनों ही खिलाड़ियों ने निराश किया है। तीसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान से बुलाए गए युवा खिलाड़ी भी असरहीन रहे हैं।

पाकिस्तान के बल्लेबाजी कोच माइकल स्मिथ ने टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी युवा खिलाड़ियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर आ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए स्मिथ ने कहा, दूसरे टेस्ट के बाद चल रही जांच के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैं इस तरह की किसी भी चीज पर टिप्पणी नहीं कर सकता। खिलाड़ियों की बात करें, तो पाकिस्तान में बहुत क्वालिटी है। हमने इसे कई सालों से देखा है और कई देशों में थोड़े-बहुत बदलाव होते हैं। यह एक ऐसा देश है जहां हमारे पास कुछ युवा खिलाड़ी के साथ कुछ अनुभवी खिलाड़ी भी हैं। यह सीखने की बात है और हम उन्हें कितनी जल्दी सीखा सकते हैं और टेस्ट के माहौल में सहज बना सकते हैं। इससे उन्हें लंबे समय में सच में मदद मिलेगी। स्मिथ ने बल्लेबाजी लाइनअप के लिए एक 'बदलाव का समय' और ज्यादा देर तक बल्लेबाजी न कर पाने की उनकी नाकामी को माना। उन्होंने कहा, हमने कुछ बहुत अच्छे संकेत दिखाए हैं। मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा सबक यह है कि हमें अपने कुछ खिलाड़ियों को कभी-कभी कुछ खास गेम प्लान के तहत घंटों तक खेलने की जरूरत है। सऊद शकील ने हमें कई बार दिखाया है। अजान अवैस और शान मसूद ने भी दिखाया है। हमें इसकी जरूरत घंटों तक है, न कि सिर्फ आधे सेशन के लिए। बल्लेबाजी कोच ने कहा, कुछ खिलाड़ियों का यह इंग्लैंड का पहला टूर है। उन्हें टेस्ट का ज्यादा अनुभव नहीं है। वे कुछ मुश्किल सबक सीख रहे हैं और उन्हें टेस्ट सर्किट पर सीखना होगा जो एक मुश्किल काम है। हमें यह पक्का करते रहना होगा कि हम कभी-कभी छोटे-छोटे अच्छे संकेत दिखा रहे हैं, लेकिन अब हमें उस कॉन्फिडेंस को फिर से पाने के लिए बड़ा खेल दिखाने की जरूरत है।

ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल के पार, अमेरिका-ईरान संघर्ष बढ़ने से वैश्विक आपूर्ति पर चिंता गहराई

नई दिल्ली, एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल बाजार में तेज उछाल देखने को मिला और ब्रेंट क्रूड 105 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित होने की आशंकाएं गहरा गई हैं। इसके साथ ही चीन की मजबूत खरीदारी और सऊदी अरब के तेल उत्पादन में भारी गिरावट ने भी कीमतों को ऊपर धकेलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड वायदा कीमतों में लगभग 2.63 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह 104 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। इससे पहले पिछले सत्र में वैश्विक मानक तेल बेंचमार्क 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया था, जो जुलाई के बाद पहली बार हुआ था। अब कीमतें मई के बाद के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। तेल की कीमतों में आई इस तेजी ने दुनिया भर में ऊर्जा आधारित महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष लंबा खिंचता है तो तेल के साथ-साथ प्राकृतिक गैस और डीजल जैसी ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों पर भी दबाव बना रह सकता है, जिसका असर वैश्विक महंगाई और आर्थिक वृद्धि पर पड़ सकता है। पिछले एक सप्ताह में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ा है। अपेक्षाकृत शांत अवधि के बाद दोनों देशों के बीच टकराव तेज हो गया है और फिलहाल हालात में तत्काल सुधार की संभावना कम दिखाई दे रही है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने कहा है कि तेहरान अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी के सामने झुकने वाला नहीं है और यदि अमेरिका ईरानी क्षेत्र पर हमले जारी रखता है तो जवाबी कार्रवाई और तेज की जाएगी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यह संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनावों के बाद तक जारी रह सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल की कीमतों में उल्लेखनीय राहत निकट भविष्य में मिलना मुश्किल हो सकता है। इन बयानों ने बाजार में यह धारणा मजबूत की है कि अब सातवें महीने में पहुंच चुका यह संघर्ष ऊर्जा बाजारों पर लंबे समय तक दबाव बनाए रख सकता है।

अगस्त की शुरूआत में दर्ज निचले स्तरों की तुलना में ब्रेंट क्रूड की कीमतों में अब तक लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी समझौते के प्रयास सफल नहीं हो सके।

बायर्न ने चैंपियंस लीग के पहले मैच में बोडो/ग्लिम्ट को 5-0 से हराया

बर्लिन, एजेंसी। जमाल मुसियाला ने बायर्न म्यूनिख की शुरूआती लाइनअप में वापसी करते हुए पहला गोल किया। इसकी मदद से जर्मन टीम ने यूईएफए चैंपियंस लीग में बोडो/ग्लिम्ट को 5-0 से हरा दिया।

बायर्न ने शुरू से ही गेंद पर कब्जा बनाए रखा, लेकिन शुरूआत में मेहमान टीम की पांच लोगों की डिफेंसिव लाइन को तोड़ने में संघर्ष किया। लुइस डियाज को पांच मिनट बाद पहला हाफ में मौका मिला, जोशुआ किमिच के क्रॉस पर उन्होंने पास से हेडर मारा, लेकिन गोलकीपर निकिता हाइकिन ने उसे बचा लिया।

किमिच का 22 मीटर का शॉट 33वें मिनट में पोस्ट के बाहर लगा, इससे पहले हाइकिन ने पहले हाफ के आखिर में मुसियाला और फिर किमिच को रोका। हाइकिन, जिन्हें बाद में सेव करते समय कमर में दिक्कत हुई, उनकी जगह हाफटाइम में जूलियन फे लुंड ने ले ली, और बायर्न को रीस्टार्ट के बाद सिर्फ दो मिनट में ही बढ़त मिल गई।

हैरी केन को रोकने की कोशिश में व ब्लॉक हो गई, लेकिन मुसियाला ने लूज बॉल को पकड़ा और अपना शॉट बाएं कोने में मार दिया। केन ने 61वें मिनट में माइकल ओलिस की फ्री-किक डिलीवरी पर फे लुंड के पास से हेडर मारकर बढ़त दोगुनी कर दी। अल्फांसो डेविस ने 77वें मिनट में 17-मीटर का स्ट्राइक कर-के मैच को आसानी से खत्म कर दिया, जिसके छह मिनट बाद ओलिस ने लेनार्ट कार्ल के पास पर बायर्न के लिए चौथा गोल किया।

बोडो/ग्लिम्ट का काम तब और मुश्किल हो गया जब 87वें मिनट में ओडिन ब्योर्टुफ्ट को पेनल्टी एरिया के पास ओलिस को गिराने के लिए रेड कार्ड दिखाया गया।

ओलिस ने फिर स्टॉपेज टाइम में अपना डबल पूरा किया और विंसेंट कोम्पनी की टीम के लिए दूसरे हाफ में पांच गोल किए।

जीत के बाद केन ने कहा, ₹हम पहले हाफ में काफी बेहतर थे। हमें बस दरवाजा खुलने तक सब्र रखना था। दूसरे हाफ की शुरूआत में किए गए गोल ने गेम को आगे बढ़ाया और हम और मजबूत हुए।

यूएस ओपनः सबालेंका ने पेगुला को हराकर फाइनल में जगह बनाई

न्यूयॉर्क, एजेंसी। टॉप सीड एरिना सबालेंका लगातार तीसरा यूएस ओपन खिताब जीतने से मात्र एक जीत दूर हैं। टॉप सीड एरिना सबालेंका ने सेमीफाइनल में तीसरी सीड अमेरिकी जेसिका पेगुला को सीधे सेटों में हराकर यूएस ओपन 2026 के महिला एकल के फाइनल में जगह बना ली है। आर्थर ऐश स्टेडियम कोर्ट पर खेले गए मुकाबले में एरिना सबालेंका ने जेसिका पेगुला को 7-5, 6-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की। सबालेंका ने अपने शानदार सर्विस गेम और जबरदस्त ग्राउंडस्ट्रोक से पेगुला को कभी भी मुकाबले में आने ही नहीं दिया। हार के साथ ही पेगुला का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों ने ज्यादा कुछ नहीं दिया, शानदार सर्व करते हुए मैच को 12वें गेम तक सर्व पर बनाए रखा, जिसमें सबालेंका 6-5 से आगे थीं। सबालेंका के जोरदार ग्राउंडस्ट्रोक के बाद पेगुला 0-40 से पीछे हो गईं और अंततः पहला सेट एरिना के नाम रहा। उन्होंने दूसरे सेट में भी मोमेंटम बनाए रखा, पेगुला के संदिग्ध दूसरे सर्व पर अटैक किया और कॉर्नर में लेजर फोरहैंड मारकर 3-1 की बढ़त के लिए जरूरी ब्रेक हासिल किया। आठवें गेम तक बाकी सेट सर्व पर ही चला, जब पेगुला ने मैच पॉइंट देने के लिए लंबा रिटर्न मारा। सबालेंका ने एक और जबरदस्त फोरहैंड मारकर जीत पक्की कर दी। साबालेंका ने अपनी जीत में सात एस और 29 विनर लगाए। टूनार्मेंट में सबालेंका का अपना सबसे अच्छा प्रदर्श जीत के बाद सबालेंका ने कहा, ₹मैं बहुत खुश हूं कि मैं ऐसा टेनिस खेल पाई। मैं जीतने के लिए बहुत बेताब थी। मैं इसे बहुत बुरी तरह चाहती थी। सबालेंका अगर यूएस ओपन 2026 का खिताब जीतने में सफल रहती हैं, तो लगातार 3 बार ये खिताब जीतने वाली क्रिस एवर्ट और सेरेना विलियम्स बाद तीसरा महिला होंगी।

यूएस ओपनः गॉफ को हराकर रायबाकिना फाइनल में, सबालेंका से खिताबी मुकाबला

न्यूयॉर्क, एजेंसी। कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने यूएस ओपन 2026 के महिला एकल फाइनल में जगह बना ली है। रायबाकिना ने अमेरिकी कोको गॉफ को हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। वह पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची हैं।

आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए एक जबरदस्त और रोमांचक मुकाबले में एक सेट से पिछड़ने के बाद एलेना रायबाकिना ने जोरदार वापसी करते हुए कोको गॉफ को 3-6, 6-4, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।

गॉफ ने अच्छी शुरूआत की और राइबाकिना पर शुरू में ही दबाव बना दिया, पहला सेट 6-3 से जीत लिया। दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी रायबाकिना ने जब पहला सेट गंवाया, उस समय ऐसा लग रहा था कि वह एक बार फिर से यूएस ओपन के फाइनल में पहुंचने का मौका चूक जाएंगी। लेकिन 27 साल की खिलाड़ी ने अपने खेल का स्तर उठाते हुए जोरदार वापसी की और अगले दो मुश्किल सेटों में अपना धैर्य बनाए रखा और जीत हासिल की। दूसरा सेट करीबी रहा, लेकिन राइबाकिना को वह ब्रेक थ्रू मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। उन्होंने इसे 6-4 से जीतकर मैच के निर्णायक सेट में पहुंचा दिया। रायबाकिना आखिरी सेट में जीत के करीब पहुंच गईं, लेकिन फिनिश आसान नहीं था। जब राइबाकिना मैच के लिए सर्व कर रही थीं, तब गॉफ ने ब्रेक बैक किया, लेकिन दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ने तुरंत जवाब दिया और मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैच के बाद रायबाकिना ने कहा, यह सिर्फ एक ब्रेक था और जाहिर है, घबराहट होती है। भले ही कभी-कभी उनकी (गॉफ) पहली सर्व अच्छी न हो, लेकिन उनकी दूसरी सर्व इतनी भारी होती है कि रैली को नियंत्रित करना मुश्किल होता है। तीसरा सेट कूल था। मैं उनकी सर्व पर थोड़ी लकी रही। कुछ डीप रिटर्न, उनकी एक गलती और यह जल्दी ही मेरे पक्ष में चला गया। यूएस ओपन 2026 का महिला एकल का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक और जोरदार होने वाला है।

डी कॉक की मदद से बारबाडोस ने सेंट किट्स को 4 विकेट से हराया

सीपीएल 2026

ब्रिजटाउन, एजेंसी। कैरेबियन प्रीमियर लीग (सीपीएल) 2026 का 32वां मुकाबला केंसिंग्टन ओवल, बारबाडोस में बारबाडोस ट्राइडेंट्स और सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स के बीच खेला गया। लो स्कोरिंग रहे इस मुकाबले को बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने 4 विकेट से जीता।

बारबाडोस ट्राइडेंट्स को जीत के लिए 119 रन का लक्ष्य मिला था। विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक की 43 गेंदों पर 2 चौकों और 2 छक्कों की मदद से खेली गई नाबाद 44 रन की पारी की बदौलत बारबाडोस ने 18 ओवर में 6 विकेट पर 120 रन बनाकर मैच 4 विकेट से अपने नाम किया। डी कॉक के साथ डेनियल सैम्स 4 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद रहे। डी कॉक की पारी अहम रही। उन्होंने एक छोर संभालकर रखा। शरफेन रदरफोर्ड ने 23, जकारी कॉर्टर ने 13 और सैड्रैक डेसकार्टेस ने 19 रन बनाए।

सेंट किट्स के लिए कप्तान जेसन होल्डर ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन उनका प्रयास टीम को जीत दिलाने के लिए काफी नहीं था। होल्डर ने 4 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए। नसीम शाह ने भी बहुत किफायती गेंदबाजी की। शाह ने 4 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट लिए। वकार सालामखेली ने 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट लिए। वानिंदु हसरंगा महंगे रहे। तीन ओवर में 35 रन लुटाने के बाद भी उन्हें विकेट नहीं मिला।

इसके पहले, बारबाडोस ट्राइडेंट्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स 20 ओवर में मात्र 118 रन पर सिमट गई। टीम के लिए सर्वाधिक 45 रन वानिंदु हसरंगा ने बनाए। हसरंगा ने 25 गेंदों की अपनी पारी में 3 छक्के और 4 चौके लगाए। इसके अलावा कप्तान जेसन होल्डर ने 24 और एलिक अथांजे ने 16 रन बनाए। सेंट किट्स की तरफ से कप्तान क्रिस ग्रीन ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट लिए। इसके अलावा, डेनियल सैम्स और गुडाकेश मोती ने 2-2 विकेट लिए। बारबाडोस इस जीत के साथ अंकतालिका में चौथे स्थान पर चली गई है। बारबडोस ने 8 मैचों में 4 जीत और 4 हार के साथ 8 अंक हासिल किए हैं। वहीं, सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स की 10वें मैच में यह छठी हार थी। टीम 7 अंक के साथ छठे नंबर पर है। लीग कुल 7 टीमें हैं।

फिनटेक वित्तीय समावेशन को दे रहा नई ऊंचाई, गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में निभा रहा अहम भूमिका

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि फिनटेक कंपनियां भारत के वित्तीय तंत्र की महत्वपूर्ण भागीदार हैं और वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आरबीआई का प्रयास फिनटेक कंपनियों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर काम करने का है, ताकि देश के हर व्यक्ति तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाई जा सकें, डिजिटल धोखाधड़ी को कम किया जा सके और बैंकिंग सेवाओं की लागत घटाई जा सके।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट (जीएफएफ) 2026 के दौरान न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि वित्तीय समावेशन, ग्राहक-केंद्रित सेवाएं और सुरक्षित डिजिटल वित्तीय प्रणाली आरबीआई की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक की मदद से वित्तीय सेवाओं को लोगों के गांवों और घरों तक पहुंचाना ही भविष्य की दिशा है।

आरबीआई गवर्नर ने कहा, फिनटेक हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है, और हमारा प्रयास है कि हम उनके साथ और अपने वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मिलकर काम करें, ताकि पूरे भारत में हम वित्तीय समावेशन, ग्राहक-केंद्रितता और डिजिटल धोखाधड़ी को कम करने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए लागत को भी कम कर सकें। उन्होंने आगे कहा, हमारा लक्ष्य इन लक्ष्यों को पूरा करने और वित्तीय प्रणाली को सभी लोगों के करीब लाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना है-उनके गांवों और घरों तक पहुंचना है। इससे पहले जीएफएफ 2026 कार्यक्रम में बोलते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। उन्होंने बताया कि देश में वर्तमान में 57 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन खाते, 25 करोड़ माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसियां और 9 करोड़ अटल पेंशन योजना लाभार्थी हैं। वहीं, यूपीआई के माध्यम से होने वाले लेनदेन का पैमाना भी लगातार बढ़ रहा है और यह आज करोड़ों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि केवल इन आंकड़ों का आकार नहीं है, बल्कि यह है कि डिजिटल वित्तीय सेवाएं आम नागरिकों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बन गई हैं।

बैंकिंग अब केवल शाखाओं तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि मोबाइल फोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे लोगों तक पहुंच रही है। संजय मल्होत्रा ने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की साझेदारी ने भारत में वित्तीय समावेशन को नई गति दी है।

सोने और चांदी धड़ाम, महंगाई के डेटा को लेकर निवेशक सतर्क

मुंबई, एजेंसी। सोने और चांदी की शुरूआत शुक्रवार को गिरावट के साथ हुई। इस दौरान दोनों कीमती धातुओं में करीब 1.10 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का 5 अक्टूबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 1,52,341 रुपए प्रति 10 ग्राम के मुकाबले 1,571 रुपए या 1.03 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,50,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। हालांकि, शुरूआती कारोबार में इसमें तेजी देखी गई और सुबह 9:48 पर यह 867 रुपए या 0.57 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,51,474 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। अब तक के कारोबार में सोना ने 1,50,695 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,51,483 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ। सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी जा रही है। चांदी का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट पिछली क्लोजिंग 2,34,099 रुपए प्रति किलो के मुकाबले 2,530 रुपए या 1.08 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 2,31,569 रुपए प्रति किलो पर खुला। अब तक के कारोबार में सोने ने 2,30,270 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 2,32,096 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 1.29 प्रतिशत की कमजोरी 4,350 डॉलर प्रति औंस और चांदी 1.99 प्रतिशत की गिरावट के साथ 63.63 डॉलर प्रति औंस पर था। जानकारों के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट की वजह मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने से डॉलर का मजबूत होना है।

भारत का एयरोस्पेस बाजार 2035 तक 61 अरब डॉलर तक पहुंचेगा, एमएसएमई के लिए खुलेंगे बड़े अवसरः राम मोहन

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि भारत का एयरोस्पेस मार्केट वर्ष 2025 के 30 अरब डॉलर से अधिक के स्तर से बढ़कर 2035 तक लगभग 61 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इसी अवधि में देश के वाणिज्यिक विमान बेड़े का आकार भी दोगुना से अधिक होकर करीब 2,050 विमानों तक पहुंच सकता है, जिससे भारतीय विनिर्माण कंपनियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए वैश्विक एयरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने का बड़ा अवसर पैदा होगा।

सीआईआई और नागर विमानन मंत्रालय की संयुक्त पहल वोर्टेक्स 2026 को संबोधित करते हुए नायडू ने कहा कि सरकार भारत में एक मजबूत एयरोस्पेस विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स निमार्ता एवियोनिक्स क्षेत्र में अवसर तलाश सकते हैं, प्रिसिजन इंजीनियरिंग कंपनियां एयरोस्पेस कलपुर्जों के निर्माण में प्रवेश कर सकती हैं और ऑटोमोबाइल उद्योग को आपूर्ति करने वाले एमएसएमई भी एयरोस्पेस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के ऑटो कंपोनेंट उद्योग, जिसका आकार आज लगभग 70 अरब डॉलर है, और मोबाइल फोन विनिर्माण क्षेत्र की सफलता एयरोस्पेस उद्योग के लिए प्रेरणादायक उदाहरण हैं। उन्होंने बताया कि आज भारत में उपयोग होने वाले लगभग 99 प्रतिशत मोबाइल फोन देश में ही निर्मित हो रहे हैं और इसी तरह की सफलता एयरोस्पेस क्षेत्र में भी हासिल की जा सकती है।

मंत्री ने कहा कि एमएसएमई निर्यात में पिछले कुछ वर्षों के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 में जहां यह लगभग 4 लाख करोड़ रुपए था, वहीं 2025 तक बढ़कर 12.4 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। वर्तमान में 1.73 लाख से अधिक एमएसएमई सीधे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एयरोस्पेस क्षेत्र की आवश्यकताओं का लगभग 80 प्रतिशत आधार भारतीय उद्योग के पास पहले से मौजूद है और शेष 20 प्रतिशत के लिए सरकार आवश्यक नियामकीय सहयोग प्रदान करेगी।

नायडू ने बताया कि भारतीय एयरलाइंस ने कुल 1,640 विमानों का ऑर्डर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में लगभग 80 करोड़ पुर्जों और कलपुर्जों की आवश्यकता होगी। यह भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक विशाल अवसर है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2035 तक भारत में हवाई यात्री यातायात में औसतन 8.9 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है, जो दुनिया की किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज वृद्धि दर होगी। उनके अनुसार, एयरोस्पेस ऐसा क्षेत्र है जहां तेजी से बढ़ता घरेलू बाजार और भारत में आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण की तलाश कर रही वैश्विक कंपनियां, दोनों एक साथ अवसर प्रदान कर रही हैं।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि केवल भारत की जरूरतें ही नहीं, बल्कि वैश्विक बाजार भी भारतीय उद्योग के लिए बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया की दो सबसे बड़ी विमान निमार्ता कंपनियों एयरबस और बोइंग के पास वर्तमान में 15,000 से अधिक वाणिज्यिक विमानों के ऑर्डर हैं। इससे भारतीय एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर पुर्जे और घटक आपूर्ति करने का अवसर मिल सकता है।

आरबीआई और सेबी ने भारत के पहले टोकनाइज्ड कॉरपोरेट बॉन्ड पायलट की शुरूआत की

मुंबई, एजेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के दौरान भारत के पहले टोकनाइज्ड कॉरपोरेट बॉन्ड पायलट का शुभारंभ किया, जिसे देश के वित्तीय बाजारों में ब्लॉकचेन तकनीक और केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) के उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत टोकनाइज्ड सिक्योरिटीज और एसेट सेटलमेंट में ब्लॉकचेन तकनीक तथा डिजिटल रुपए (सीबीडीसी) का उपयोग किया जाएगा। शुरूआती चरण में यह व्यवस्था कॉरपोरेट बॉन्ड पर केंद्रित रहेगी, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट तक भी किया जा सकता है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अब केवल एक उद्योग सम्मेलन नहीं रह गया है, बल्कि यह ऐसा मंच बन चुका है जहां वित्तीय क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्ष भविष्य की वित्तीय व्यवस्था को आकार देने वाले विचारों पर चर्चा करते हैं।

उन्होंने भारत में डिजिटल वित्तीय परिवर्तन की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में अब 57 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते, 25 करोड़ सूक्ष्म बीमा पॉलिसियां और अटल पेंशन योजना के तहत 9 करोड़ लाभार्थी हैं। वहीं, यूपीआई पर लगभग 80 करोड़ लेनदेन दर्ज किए जा रहे हैं।

मल्होत्रा ने कहा कि इन उपलब्धियों की सबसे बड़ी विशेषता केवल उनका पैमाना नहीं है, बल्कि यह है कि डिजिटल वित्त अब लोगों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सहयोग से देश में व्यापक वित्तीय समावेशन संभव हुआ है।

उन्होंने कहा कि अब अगला लक्ष्य वित्तीय सेवाओं को हर व्यक्ति तक, हर समय और हर स्थान पर उपलब्ध कराना होना चाहिए। उनके अनुसार, पारंपरिक वित्तीय संस्थानों को महिलाओं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और किसानों तक छोटे ऋण पहुंचाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में फिनटेक कंपनियां तकनीक के माध्यम से इन कमियों को दूर कर सकती हैं और वित्तीय समावेशन को और मजबूत बना सकती हैं।

प. बंगाल : नाबालिग गर्भधारण मामलों के लिए बनेगी एसओपी

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार कर रहा है कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों (शादीशुदा होने पर भी) के गर्भवती होने के मामलों को कैसे संभाला जाए।

यह पहल मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की इस घोषणा के बाद की गई है कि अब से 18 साल की उम्र से पहले मां बनने वाली लड़कियों के पतियों पर 'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज' (पॉक्सो) एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और राज्य सरकार उनके खिलाफ खुद (सूमो-मोटो) मामले दर्ज करेगी।

स्वास्थ्य विभाग ने बनाई विशेषज्ञ समिति

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में एसओपी तैयार करने के लिए नौ सदस्यों की एक एक्सपर्ट कमेटी पहले ही बना दी गई है।

इस एक्सपर्ट कमेटी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रमुख देबाशीष दास और पांच प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ उलुबेरिया मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉ. संजय भट्टाचार्य, एनआरएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉ. सौरव चटर्जी, रायगंज मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की डॉ. तुलिका झा, रामपुरहाट मेडिकल एंड हॉस्पिटल की डॉ. शैली सेठ और अपोलो हॉस्पिटल के डॉ. भास्कर पाल शामिल हैं।

कमेटी में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मातृ स्वास्थ्य की डिप्टी डायरेक्टर श्यामली रुद्र, परिवार नियोजन अधिकारी शाश्वती नाग और पूर्वी मेदिनीपुर जिले की पब्लिक हेल्थ एंड नर्सिंग ऑफिसर सीमा माइती भी शामिल हैं। कमेटी की पहली बैठक 18 सितंबर को होगी।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सरदवत मुखोपाध्याय के अनुसार पश्चिम बंगाल में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के गर्भवती होने की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई नाबालिग लड़की 18 साल से कम उम्र में गर्भवती हो जाती है तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती है कि गर्भावस्था के दौरान उसकी मौत हो सकती है, इसलिए ऐसे मामलों को कैसे संभाला जाए, इस पर एक एसओपी होना जरूरी है।

पता चला है कि प्रस्तावित एसओपी में कई अहम मुद्दों की जानकारी जैसे कि मां को होने वाले जोखिमों की पहचान, नियमित एंटीनेटल चेकअप (गर्भावस्था के दौरान जांच), एनीमिया और कुपोषण का इलाज, जरूरत पड़ने पर बड़े मेडिकल सेंटरों में रेफर करना, सुरक्षित डिलीवरी और डिलीवरी के बाद मां और बच्चे की निगरानी शामिल होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा, ₹नई एसओपी में यह बताया जाएगा कि प्रेग्नेंसी की पुष्टि होने के तुरंत बाद किशोर लड़की को स्त्री रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) और प्रसूति रोग विशेषज्ञ (ऑब्स्टेट्रिशियन) के पास ले जाया जाए और उसे प्रसव-पूर्व देखभाल (एंटीनेटल केयर) के दायरे में लाया जाए।

सिर्फ स्वाद नहीं, सेहत का आधार है आयुर्वेद आहार, आयुष मंत्रालय ने बताया महत्व

नई दिल्ली, एजेंसी। आज के समय में लोग अपने खान-पान को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। क्या खाना चाहिए, किस तरह का भोजन हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए और पारंपरिक खान-पान को किस नजरिए से देखा जाए, इन सवालों पर लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। ऐसे में आयुर्वेद आहार की अवधारणा को समझना जरूरी हो जाता है।

आयुष मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि आयुर्वेद आहार यानी ऐसा आहार, जिसकी अवधारणा आयुर्वेद के सिद्धांतों और पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी है। इसे समझने के लिए केवल भोजन पर ध्यान देना काफी नहीं है। इसके साथ हमारी परंपरा और भोजन से जुड़े तय मानकों को भी समझना जरूरी है।

आयुर्वेद आहार के लिए एक निर्धारित नियामक व्यवस्था भी मौजूद है। खाद्य सुरक्षा और मानक (आयुर्वेद आहार) विनियम, 2022 के तहत आयुर्वेद आहार के लिए एक नियामक ढांचा तैयार किया गया है। इसमें श्रेणी ए की व्यवस्था भी शामिल है। इसका उद्देश्य आयुर्वेद आहार के उत्पादन और उससे जुड़ी जानकारी को एक व्यवस्थित और जिम्मेदार ढांचे में लाना है।

आयुर्वेद आहार को आसान भाषा में समझने के लिए तीन बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं- आहार, परंपरा और मानक।

पहला है आहार। इसका सीधा मतलब है कि हम क्या खाते और पीते हैं। हमारे रोजमर्रा के भोजन में शामिल सभी चीजें हमारी आहार व्यवस्था का हिस्सा हैं। आयुर्वेद में भोजन को केवल भूख मिटाने का साधन नहीं माना जाता, बल्कि खान-पान और जीवनशैली को भी महत्वपूर्ण माना गया है।

दूसरा है परंपरा। भारत में भोजन से जुड़ा ज्ञान और तरीके सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहे हैं। अलग-अलग इलाकों में मौसम, स्थानीय उपलब्धता और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर भोजन तैयार करने और खाने के अलग-अलग तरीके देखने को मिलते हैं। यही पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान आयुर्वेद आहार को समझने में अहम भूमिका निभाता है।

तीसरा है मानक। किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन और उसके बारे में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए स्पष्ट नियम और जिम्मेदार व्यवस्था जरूरी होती है। मानक इसी व्यवस्था का आधार हैं। ये भोजन के उत्पादन और उससे जुड़ी जानकारी को एक तय ढांचे के भीतर रखने में मदद करते हैं।

एक नजर

औषधीय गुणों से भरपूर है बेल का पेड़, आयुष मंत्रालय ने बताए इसके चमत्कारी गुण

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत में पेड़-पौधों का महत्व सिर्फ पर्यावरण तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि प्राचीन समय से ही कई पौधों का इस्तेमाल औषधीय जरूरतों के लिए भी किया जाता रहा है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पौधा है बेल, जिसे संस्कृत में बिल्व और अंग्रेजी में वुड एप्पल कहा जाता है। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, आयुष मंत्राल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेल के औषधीय महत्व से जुड़ी जानकारी साझा की है। वनस्पति विज्ञान में बेल का नाम एगल मामेलोस है और यह रैसेसी परिवार से संबंधित है। यह पेड़ मुख्य रूप से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया का मूल निवासी माना जाता है। भारत में यह सूखे जंगलों और मैदानी क्षेत्रों में आमतौर पर देखने को मिलता है। खास बात यह है कि बेल अलग-अलग तरह की जलवायु में भी आसानी से पनप सकता है और कम उपजाऊ मिट्टी में भी अच्छी तरह बढ़ने की क्षमता रखता है। बेल का पेड़ मध्यम आकार का पर्णपाती वृक्ष होता है, जिसकी ऊंचाई करीब 15 मीटर तक पहुंच सकती है। इसकी पत्तियां तीन पत्तियों वाले समूह यानी त्रिपर्णी होती हैं और इनमें हल्की सुगंध होती है। बेल के फूल हरे-सफेद रंग के और सुगंधित होते हैं। इसका फल कच्चा और सूखने के बाद भी कई पारंपरिक उपयोगों में काम आता है। आयुर्वेद में बेल को लंबे समय से महत्वपूर्ण औषधीय पौधे के रूप में देखा जाता है। इसके फल, पत्तियां और जड़ विभिन्न पारंपरिक औषधीय उपयोगों में इस्तेमाल किए जाते हैं। विशेष रूप से बेल के फल को पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं में उपयोगी माना जाता है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के अनुसार इसमें एंटी-डायरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीमाइक्रोबियल जैसे औषधीय गुण बताए गए हैं।

अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो 50 प्रतिशत बीमारी खत्म हो जाएगी

नई दिल्ली, एजेंसी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद (एआईआईए) के डायरेक्टर, प्रोफेसर (वैद्य) प्रदीप कुमार प्रजापति ने गुरुवार को आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि निकारागुआ के एम्बेसडर नादेस्का कुथबर्ट ने एआईआईए का दौरा किया और दोनों देशों के बीच आयुर्वेद एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक एमओयू साइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम पूरे देश को लेकर एक जन आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद में वर्णित आहार-विहार की कल्पना को लोगों को समझा सकें। बहुत से देशों में इस प्रकार की पौराणिक चीजों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और साक्ष्य हैं, हम उसकी भी बात करते हैं, क्योंकि बिना उसके लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए हमारे पास जितने भी कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट और विकसित देशों में जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को वैज्ञानिक पृष्ठभूमि और साक्ष्य के साथ वर्णित करें ताकि यह आम लोगों तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि जब हम जन आंदोलन की बात करते हैं, तो घर-घर आयुर्वेद और प्रत्येक व्यक्ति आयुर्वेद से जुड़े, यह हमारा लक्ष्य होता है। जब हम आहार और विहार को संतुलित कर लेंगे, तब हमें औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं कि आजकल जो हमारा काम करने का ढंग है, लाइफस्टाइल है, जो विकास है, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई-फाई रूप में आ चुकी है। लोग कितनी भी कोशिश करें, 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम पर चले ही जाते हैं। स्क्रीन टाइम की वजह से लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद और योग अपनाना होगा। लोगों की लाइफस्टाइल आजकल खाने, सोने, काम करने और घूमने तक सीमित रह गई है। ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए दिनचर्या में आयुर्वेद और योग को अपनाना बहुत अहम हो गया है। प्रोफेसर ने कहा कि इसके लिए हमें अपनी दिनचर्या और ऋतुचर्या को संतुलित करने की आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों द्वारा बताई गई बातें आज भी बहुत ज्यादा लाभकारी हैं।

आयुर्वेद में घरेलू औषधीय पानी का महत्व - 6 प्रभावी नुस्खे, यहां देखें

नई दिल्ली, एजेंसी। आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चीजों और संतुलित जीवनशैली को महत्व दिया जाता है। हमारे रसोई घर में मौजूद कई सामान्य चीजों का उपयोग पारंपरिक रूप से छोटी-मोटी तकलीफों में किया जाता रहा है। इन्हीं में से हैं ये 6 औषधीय पानी इस प्रकार वर्णित हैं ।

1. जीरा पानी
जीरा को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उबालकर पीना पाचन के लिए अमृत समान है। 10 से 15 दिन लगातार पीने से अपच और गैस की समस्या नहीं होती और मेटाबॉलिज्म तेज होने से वजन घटने में मदद मिलती है।

2. मेथी पानी
मेथी दाने मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष लाभकारी हैं। 15 से 20 दिन लगातार पीने से शुगर लेवल नियंत्रित रहता है, इन्सुलिन सेंसिटिविटी सुधरती है और जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है।

3. धनिया पानी
गर्मी के मौसम में शरीर की गर्मी शांत करने के लिए धनिया पानी उत्तम है। 7 से 10 दिन पीने से पेशाब की जलन, बार-बार पेशाब आना और शरीर की आंतरिक गर्मी में राहत मिलती है। यह मधुमेह में भी सहायक है।

4. अजवाइन पानी
पेट दर्द, गैस, अफारा के लिए अजवाइन पानी सबसे तेज काम करता है। 10 से 12 दिन पीने से पाचन अग्नि प्रदीप्त होती है और पेट हल्का रहता है।

5. सौंफ पानी
सौंफ शीतल और हार्मोन संतुलन में मददगार है। 15 दिन लगातार पीने से हार्मोन संतुलन मजबूत होता है, आंखों की रोशनी और पेट की जलन में विशेष राहत मिलती है। महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी।

6. दालचीनी पानी
दालचीनी मेटाबॉलिज्म बूस्टर है। 10 दिन लगातार पीने से मेटाबॉलिज्म सुधरता है, वजन घटता है और बैड कोलेस्ट्रॉल (छउ्छ) कम करने में मदद मिलती है।

ध्यान रखने योग्य बातेः
1. ये घरेलू नुस्खे हैं, किसी गंभीर बीमारी का स्थायी इलाज नहीं हैं।
2. गर्भवती महिलाएं, पथरी या अल्सर के रोगी इनका सेवन वैद्य से पूछकर ही करें।

मनोरंजन

शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थीं परिणीति चोपड़ा, ट्रेलर लांच पर किया खुलासा

मुंबई, एजेंसी। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की वेब सीरीज 'शकः ट्रस्ट नो वन' के मेकर्स ने गुरुवार को ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। यह एक ऐसी मां की कहानी है जो पिछले नौ सालों से अपने लापता बच्चे को ढूंढ रही है। यह सीरीज भरोसा, शक और धोखे जैसे मुद्दों को दिखाती है, जब परिणीति चोपड़ा की तलाश एक अनोखा मोड़ ले लेती है। ट्रेलर में एक मां को अपने लापता बच्चे की लगातार तलाश करते हुए दिखाया गया है। वह अपने अंदर की आवाज और पक्के विश्वास से प्रेरित होकर विश्वास जताती है कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा है। नौ साल की लंबी तलाश एक ऐसे सच को सामने लाने की कोशिश में बदल जाती है जो साफ नजर आता है, साथ ही उसे

एक डरावने सवाल का सामना करने के लिए मजबूर करती है, 'क्या वह अपने सबसे करीबी लोगों पर भरोसा कर सकती है?

ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने बताया कि वह और उनके पति राघव चड्ढा इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि सीरीज पर काम करने के दौरान वह प्रेग्नेंट थीं। उन्होंने कहा, ₹राघव और मैं हमेशा इस बारे में मजाक करते हैं कि भगवान का शुक्र है कि मैं इस प्रोजेक्ट में इन मेकर्स के साथ प्रेग्नेंट थी, किसी और फिल्म में किसी और मेकर के साथ नहीं क्योंकि हमें प्रेग्नेंसी के बारे में पहले से पता नहीं था। हमें शूट शुरू होने के बाद ही पता चला और फिर प्रोफेशनलिज्म का दबाव भी आता है। आप नहीं चाहते कि आपके प्रोजेक्ट पर कोई असर पड़े और मेकर्स ने मेरे आराम और सेहत का पूरा ख्याल रखा था और मेरे सीक्वेंस में जरूरी बदलाव भी किए थे। अभिनेत्री ने शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया, ₹हम सीरीज की शूटिंग के लिए पहले से शिमला के चैल में थे और मेकर्स को मुझे ये खबर देनी थी और मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो हम संभाल लेंगे और उन्होंने सच में मेरा एक बच्ची की तरह ख्याल रखा था। मैंने देखा कि पूरी टीम क्रिएटिव तौर पर और भी एक्टिव हो गई। उन्होंने मेरे आराम के लिए एक्शन सीक्वेंस में बदलाव किए, बिना क्रिएटिविटी को खराब किए। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा का कहना है कि वे खुद खुशकिस्मत मानती हैं कि उन्हें इतने अच्छे प्रोड्यूसर मिले हैं। अभिनेत्री ने कहा, ₹एक प्रोड्यूसर के तौर पर, यहीं पर आप किस्मत वाले होते हैं। हम शिमला और चैल में बंगलों और अजीबोगरीब लोकेशन्स पर शूट कर रहे थे और हमारी लोकेशन्स बहुत दूर थीं, तो हमारी प्रोड्यूसर ने मेरे लिए सेट पर ही रहने का इंतजाम करवाया था।

10 सितंबर को लास वेगास में घोषित हुआ था 'अनुपम खेर डे'

मुंबई, एजेंसी। दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर के लिए 10 सितंबर का दिन बेहद खास है। कई दशक लंबे अपने करियर में उन्होंने फिल्मों से लेकर अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स तक अपनी अलग पहचान बनाई है। इस सफर में उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान मिले लेकिन एक सम्मान ऐसा है, जिसे वह आज भी बेहद खास मानते हैं। दरअसल, लास वेगास में 10 सितंबर को 'अनुपम खेर डे' घोषित किया गया था। इस खास मौके को याद करते हुए अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया और बताया कि छोटे शहर शिमला से निकलकर मनोरंजन की दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक लास वेगास में अपने नाम का दिन घोषित होना उनके लिए किसी सपने जैसा है।

तेलुगु स्टार नानी की 'द पैराडाइज' की शूटिंग पूरी, 24 सितंबर को रिलीजिंग

हैदराबाद, एजेंसी। इंडस्ट्री के सूत्रों की मानें तो, डायरेक्टर श्रीकांत ओडेला की बेसब्री से इंतजार की जा रही एक्शन एंटरटेनर फिल्म 'द पैराडाइज', जिसमें तेलुगु स्टार नानी मुख्य भूमिका में हैं, की शूटिंग अब पूरी हो गई है।

सूत्रों का कहना है कि फिल्म की यूनिट ने प्रोडक्शन का हिस्सा पूरा कर लिया है और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम भी जोरों पर है। एसएलवी सिनेमाज के बैनर तले सुधाकर चेरुकुरी द्वारा निर्मित यह फिल्म 24 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म का प्रीमियर इस साल 23 सितंबर को होना है। इस बीच, निर्माताओं ने गुरुवार को फिल्म से नानी की एक नई तस्वीर जारी कर-के प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा दिया। फिल्म न केवल अभिनेता की आकर्षक उपस्थिति के लिए, बल्कि

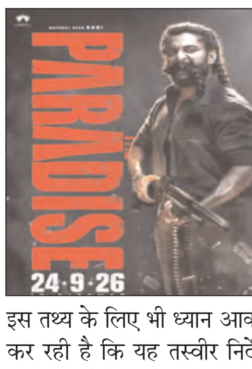

इस तथ्य के लिए भी ध्यान आकर्षित कर रही है कि यह तस्वीर निर्देशक श्रीकांत ओडेला के मोबाइल का स्क्रीनशॉट थी। हाल में जारी किए गए पोस्टर में, नानी लंबे बालों, घनी दाढ़ी और गहरे रंग की पोशाक के साथ एक पीरियड लुक में नजर आ रहे हैं। वह एक बंदूक पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वह गहरी नजरों से घूर रहे हैं। 'द पैराडाइज' 26 मार्च, 2026 को एक भव्य रिलीज के लिए निर्धारित थी। हालांकि, इसके निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज को पहले 21 अगस्त और फिर 24 सितंबर तक स्थगित करने का फैसला किया।

निर्माताओं ने कुछ समय पहले एक टीजर जारी किया था, जिसने प्रशंसकों के उत्साह को बढ़ा दिया है। टीजर की शुरूआत एक वॉयसओवर से होती है जिसमें पूछा जाता है, 'अब से, यह जगह किसकी है?' नानी काफी नाटकीय अंदाज में कलाबाजी दिखाते हुए उनके आगमन की घोषणा करते नजर आ रहे हैं। फिर मोहन बाबू को दिखते हैं, जो प्रतिपक्षी की भूमिका निभाते हैं, लोगों को 'स्वर्ग के मेरे प्यारे लोग' कहते हैं। टीजर ने यह बताया कि फिल्म एक गंभीर, एक्शन थ्रिलर होगी, जो अत्याचार के खिलाफ विद्रोह में उत्पीड़ितों का नेतृत्व करने वाले नानी के इर्द-गिर्द घूमेगी।

'बिग बॉस' ने निरहुआ से मिलवाया और बदल गई किस्मत आम्रपाली दुबे ने सुनाई भोजपुरी फिल्मों में आने की कहानी

मुंबई, एजेंसी। आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्रियों में शामिल हैं। दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया है। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्मों में काम किया है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वह इस इंडस्ट्री में सिर्फ एक फिल्म करने के इरादे से आई थीं और उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही एक फिल्म उनके करियर की नई पहचान बन जाएगी।

दरअसल, आम्रपाली ने 'बिग बॉस 20' के घर में अपनी इस दिलचस्प कहानी का खुलासा किया और बताया है कि कैसे 'बिग बॉस' उनके लिए एक तरह से कास्टिंग एजेंसी बन गया। घरवालों से बातचीत में आम्रपाली ने बताया कि उनकी भोजपुरी फिल्मों में एंट्री के पीछे 'बिग बॉस 6' का बड़ा हाथ रहा। 'बिग बॉस 6' में दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' बतौर कंटेस्टेंट पहुंचे थे। उसी सीजन में अभिनेता संतोष शुक्ला भी शो का हिस्सा थे। आम्रपाली पहले संतोष शुक्ला के साथ टीवी पर काम कर चुकी थीं। आम्रपाली ने कहा, '''बिग बॉस 6' के दौरान दिनेश लाल यादव अपनी आने वाली फिल्म को लेकर संतोष शुक्ला से बात कर रहे थे। उन्हें अपनी फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी। वह ऐसी लड़की चाहते थे, जिसे भोजपुरी दर्शक आसानी से अपना सकें। दिनेश लाल उस समय 'निरहुआ हिंदुस्तानी' के लिए एक नई अभिनेत्री की

तलाश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, ''उस वक्त मैं भोजपुरी फिल्मों में लंबा करियर बनाने के बारे में सोच भी नहीं रही थीं। मेरा इरादा सिर्फ एक फिल्म करने का था। फिल्म पूरी करने के बाद मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ देना चाहती थीं। मुझे लगता था कि मैं एक फिल्म करूंगी और फिर अपने दूसरे काम पर ध्यान दूंगी। लेकिन फिल्म की सफलता ने मेरे फैसले बदल दिए। साल 2014 में रिलीज हुई 'निरहुआ हिंदुस्तानी' में आम्रपाली दुबे ने दिनेश लाल यादव के साथ काम किया था। फिल्म रिलीज होने के बाद दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिला।

एक शादी में पहुंचीं और बदल गई किस्मत, यशराज की फिल्म से ट्यूलिप जोशी का बॉलीवुड डेब्यू

मुंबई, एजेंसी। ट्यूलिप जोशी उन अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं, जिनकी बॉलीवुड में एंट्री एक खास संयोग से हुई थी। 2002 में जब वह पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आईं तो उनके सामने यशराज फिल्म्स जैसा बड़ा बैनर था और फिल्म थी 'मेरे यार की शादी है'। नई एक्ट्रेस के लिए इससे बेहतर शुरूआत और क्या हो सकती है। फिल्म में उनके साथ उदय चोपड़ा, जिम्मी शेरगिल और बिपाशा बसु जैसे कलाकार थे।

ट्यूलिप की मासूमियत और सादगी भरे अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन इस डेब्यू के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि ट्यूलिप खुद फिल्म इंडस्ट्री में आने की योजना नहीं बना रही थीं। एक शादी में जाना उनके लिए ऐसा मोड़ लेकर आया, जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी।

ट्यूलिप जोशी का जन्म 11 सितंबर 1979 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता गुजराती हिंदू थे, जबकि उनकी मां अर्मेनियाई-लेबनीज क्रिश्चियन थीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्यूलिप ने साल 2000 में फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वह इस प्रतियोगिता की विजेता नहीं बनीं, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में उनके लिए रास्ते खुलने लगे। उस समय उनका सपना एक्ट्रेस बनना नहीं था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वह स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहती थीं।

ट्यूलिप की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब वह एक शादी में शामिल होने गई थीं। यह शादी फिल्ममेकर आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना की थी। ट्यूलिप वहां लड़की वालों की तरफ से शामिल हुई थीं। शादी में उनकी पर्सनैलिटी पर आदित्य चोपड़ा की नजर पड़ी। इसके बाद उन्हें फिल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट देने का मौका मिला। ट्यूलिप ने भी बिना ज्यादा सोचे ऑडिशन दिया और उनका सेलेक्शन हो गया। इस तरह उन्हें सीधे यशराज फिल्म्स के बड़े बैनर के साथ काम करने का मौका मिला।

साल 2002 में 'मेरे यार की शादी है' रिलीज हुई। फिल्म में ट्यूलिप के साथ उदय चोपड़ा मुख्य भूमिका में थे। फिल्म ने उन्हें नई पहचान दी। बताया जाता है कि फिल्म में अपनी लाइन्स हिंदी में बोलने में उन्हें परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने हिंदी की ट्यूशन ली थी।

पहली फिल्म की सफलता के बाद ट्यूलिप 'दिल मांगे मोर' में शाहिद कपूर और आयशा टाकिया के साथ नजर आईं। इसके बाद उन्होंने 'मातृभूमिः ए नेशन विदाउट वीमेन' जैसी गंभीर फिल्म की, जिसमें उन्होंने कल्कि का किरदार निभाया। फिल्म में उनके काम को काफी सराहना मिली और अलग-अलग फिल्म फेस्टिवल में सम्मान भी मिला। ट्यूलिप ने बाद में खुद कहा था कि 'मातृभूमि' के बाद उन्होंने खुद में एक कलाकार के तौर पर बदलाव महसूस किया। ट्यूलिप का सफर सिर्फ हिंदी फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। वह 'मिशन 90 डेज', 'धोखा', 'सुपरस्टार', 'डैडी कूल', 'रनवे', 'बच्चन', 'जट्ट एयरवेज' और 'जय हो' जैसी फिल्मों में नजर आईं।